बैंक राष्ट्रीयकरण की स्वर्ण जयंती: एक समीक्षा

07
अध्याय

''देश के पूंजी परिवर्धन ही नहीं, बैंकिंग गतिविधियों के सर्वाधिक न्यायसंगत उपयोग से मौजूदा पूंजी के बड़े भाग को सक्रिय करके और उसकी उत्पादकता बढ़ाकर देश की औद्योगिक अभिवृद्धि की जा सकती है।''

-एडम स्मिथ

वर्ष 2019 में, भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का 50वां वर्ष पूर्ण हुआ। इसलिए यह उचित ही होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में कार्य करने वाले 389,956 अधिकारियों, 295,380 लिपिकों और 121,647 सहायक कर्मचारियों की कार्यासिद्धियों की खुशी मनायी जाए। साथ-ही-साथ, यह भी उचित होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाए, वर्ष 1969 से ही, भारत दिन दूनी और रात चौगुनी प्रगति करते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। तो भी, अर्थव्यवस्था के आकार की दृष्टि से भारत का बैंकिंग क्षेत्र समानुपात में विकसित नहीं हो पाया है। उदाहरण के तौर पर, विश्व के 100 शीर्ष बैंकों में भारत का केवल एक ही बैंक आता है और यह स्थिति भारत को उन अनेक देशों की श्रेणी में ले जाती है जिनकी अर्थव्यवस्था का आकार भारत के मुकाबले में कई-कई गुना तक कम है जैसेकि-फिनलैंड (लगभग 1/11वां भाग), डेनमार्क (1/8वां भाग), नार्वे (1/7वां भाग), आस्ट्रिया (लगभग 1/7वां भाग) और बेल्जियम (लगभग 1/6वां भाग)। स्वीडन और सिंगापुर जैसे देशों, जिनकी अर्थव्यवस्था का आकार भारतीय अर्थव्यवस्था के क्रमश: 1/6वें और 1/8वें भाग के बराबर है, के विश्व स्तरीय बैंकों की संख्या भी भारत से तीन गुनी अधिक है। एक विशाल अर्थव्यवस्था की सवृद्धि में सहायता देने के लिए एक दक्ष बैंकिंग क्षेत्र की आवश्यकता होती है। ऐतिहासिक रूप से पिछले 50 वर्षों में शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं को सदैव उनके बैंकिंग की ओर से उचित सहारा मिला है। चूंकि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत है अत: भारतीय अर्थव्यवस्था को सहारा देने और इसके आर्थिक विकास का पोषण करने की जिम्मेदारी इन्हीं पर है। परंतु, यदि कार्यनिष्पादन के प्रत्येक पैरामीटर के हिसाब से देखें तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपने समकक्ष समूहों की तुलना में दक्षता का अभाव है। विगत में, नरसिम्हन समिति (1991, 1997), राजन समिति (2007) और पी जे नायक समिति (2014) ने सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की दक्षता बढ़ाने के लिए अनेक सुझाव दिए हैं। इस समीक्षा में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की दक्षता के संवर्धन हेतु बैंकिंग कार्यों में वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) के और समस्त स्तरों पर कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व के उपयोग का सुझाव दिया गया है। इनसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को और अधिक दक्षता प्राप्त होगी और वे 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की दिशा में राष्ट्र की यात्रा में कुशलतापूर्वक सहयोग करने में समर्थ हो सकेंगे।

7.1 भारत वर्ष 1969 में चलाए गए बैंक राष्ट्रीयकरण कार्यक्रम के वर्ष 2019 में 50 वर्ष पूरे हो गए। इसलिए यह उचित ही है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में कार्य करने वाले 389,956 अधिकारियों, 295,380 लिपिकों ओर 121,647 सहायक कर्मचारियों की कार्यसिद्धियों की खुशी मनाई जाए। चूंकि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत है अत: भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की स्थिति का एक मूल्यांकन करना उपयुक्त होगा। यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बैंकिंग क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाते हैं तथापि, जब इनकी तुलना इनके समवर्तियों से की जाती है तो कार्यनिष्पादन के मानकों पर ये काफी पिछड़ी स्थिति में पाए जाते हैं।

7.2 चित्र 1 दर्शाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था के आकार की दृष्टि से इसके बैंक आनुपातिक रूप से छोटे हैं। वर्ष 2019 में, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमारा सर्वोच्च श्रेणीप्राप्त बैंक भारतीय स्टेट बैंक-विश्व में 55वे स्थान पर है जोकि काफी नीचे है तथा विश्व के 100 बैंकों में कोई स्थान पाने वाला एकमात्र बैंक है। विश्व के 100 शीर्ष बैंकों में भारत का केवल एक बैंक है जिसे इस विशेषता के कारण उन देशों के समूह में रखा जाता है जिनकी अर्थव्यवस्था के आकार भारत की अर्थव्यवस्था के न्यून अंश के समान ही है जैसे फिनलैंड (1/11वां), डेनमार्क (1/8वां), नार्वे (1/7वां), आस्ट्रिया (1/7वां) और बेल्जियम (1/6वां)। स्वीडन और सिंगापुर जैसे देश, जिनकी अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था के आकार के क्रमश: लगभग 1/6वे और 1/8 वें भाग के बराबर है, वैश्विक स्तर पर भारत की तुलना में तीन गुना अधिक बैंक वाले देश हैं।

चित्र 1: वैश्विक शीर्ष 100 बैंकों में बैंकों की संख्या (2019)

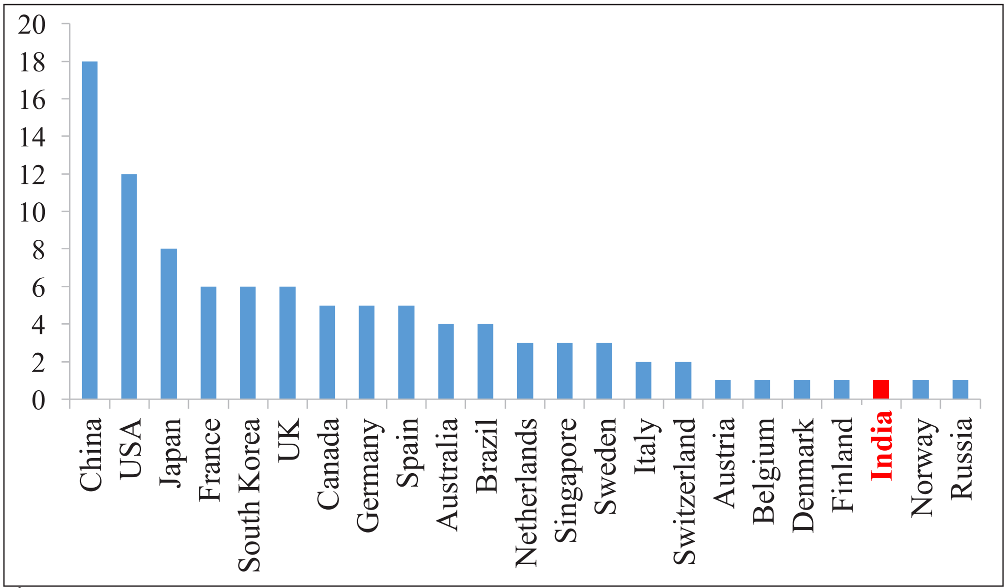

स्रोत: विकिपीडिया

7.3 चित्र 2, भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार की तुलना में भारतीय बैंकों के इस विषमानुपाती बौनेपन को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है। विश्व के 100 शीर्ष बैंकों में कई बैंकों की मौजूदगी नहीं होना तथा भारत की अर्थव्यवस्था का आकार स्पष्ट तौर पर इंगित करता है कि यह नकारात्मक पक्ष पर एक महत्वपूर्ण बाह्यशायी है। सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में समानुपातिक रूप से बड़े बैंक हैं तथा विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में चीन के 18 बैंकों का होना सकारात्मक पक्ष पर उसका बाह्यशायी होना दर्शाता है। इसी प्रकार चित्र-3 दर्शाता है कि निजी क्षेत्र में बैंक साख की पैंठ का देश की जीडीपी के अनुसार अंकन करने से भारत में साख की पैंठ का आंकलन हो जाता है। क्योंकि भारत में बैंक साख की पैंठ का अपंकलन हो जाता है। क्योंकि भारत

[1] स्रोत: आरबीआई डाटा

में यह साख मुख्यत: बैंक ही प्रदान करते हैं। रेखाचित्र 4 बताता है कि यह अतिन्यून आनुपातिक पैंठ केवल हमारी विशाल जन संख्या के कारण नहीं हैं यह सत्य है कि अधिक जनसंख्या के कारण साख पैंठ का आकार कम हो जाता है किन्तु भारत में तो यह न्यूनता जनसंख्या की तुलना में अत्याधिक न्यून हो गई है। संक्षेप में, चित्र 1-4 देश की अर्थव्यवस्था के आकार ख्जीडीपी,, अर्थव्यवस्था के विकास ख्प्रति व्यक्ति जीडीपी, और जनसंख्या जैसा विशेषताओं की तुलना में हमारे देश के बैंक क्षेत्र के बौनेपान को स्पष्ट कर रहे हैं।

चित्र 2: देश की जीडीपी तथा विश्व के शीर्ष 100 में उसके बैंकों की संख्या

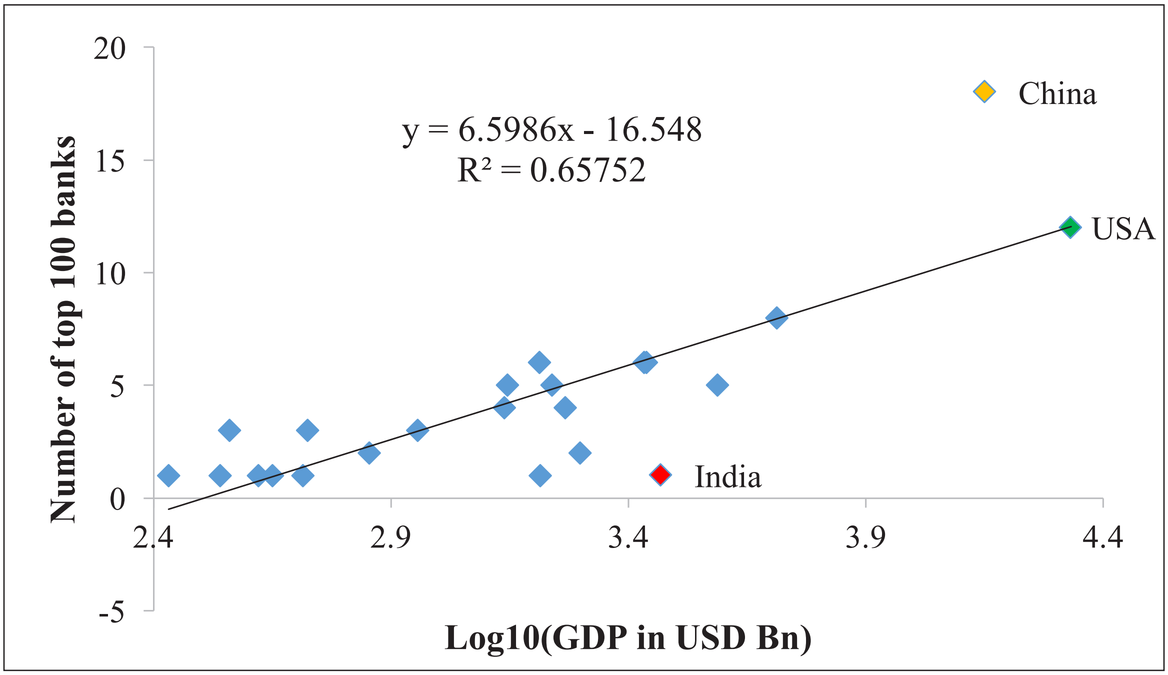

स्रोत: शीर्ष 100 बैंकों के लिए विकिपीडीया और आईएमएफ से प्राकलित जीडीपी 2019

चित्र 3: देश की प्रतिव्यक्ति जीडीपी और साख की पैंठ

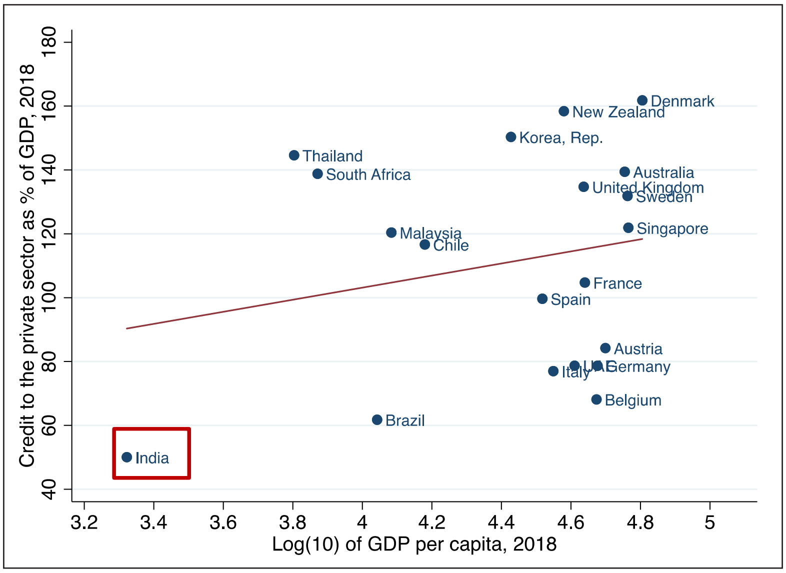

स्रोत: विश्व बैंक डब्ल्यूडीआई डाटाबेस

चित्र 4: देश की जनसंख्या और साख की पैंठ

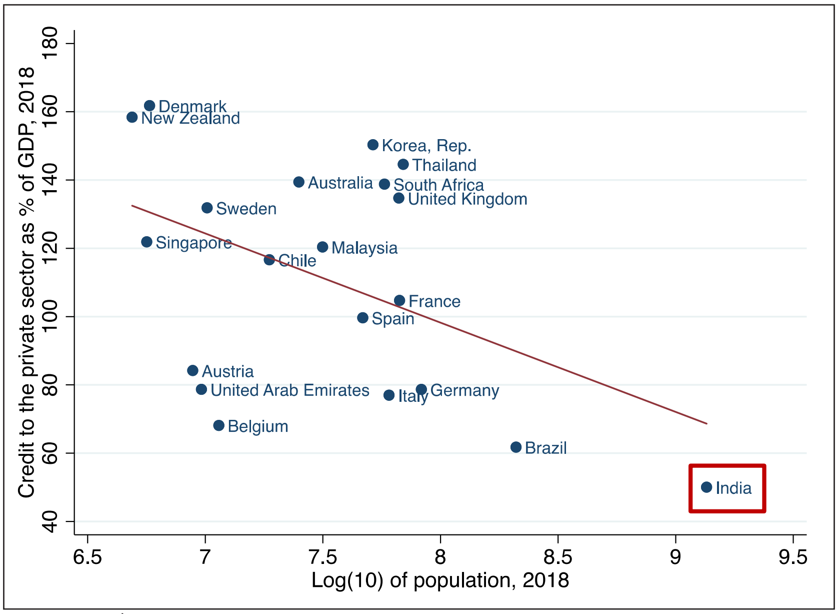

स्रोतः विश्व बैंक डब्ल्यूडीआई डाटाबेस

7.4 एक बड़ी अर्थव्यवस्था को अपनी वृद्धि को अपनी वृद्धि का समर्थन करने के लिए एक कुशल बैंकिंग क्षेत्र की आवश्यकता होती है। चित्र-3 दर्शाता है कि पीएसबी के बीच ऋण वृद्धि में वर्ष-2013 के बाद से न केवल तेजी से गिरावट आई है, बल्कि वर्ष 2016 के बाद से तो यह क्षेत्र जोशरहित भी हो गया है। भले ही वर्ष 2010 और 2019 के बीच एनपीबी ने प्रति वर्ष 15 प्रतिशत और 29 प्रतिशत के बीच साख वृद्धि दर्ज की परंतु फिर भी वर्ष 2014 के बाद पीएसबी की साख वृद्धि अवरुद्ध होकर वर्ष 2019 में एकल अंकों, 4.03 प्रतिशत तक पहुंच गई, जबकि वर्ष 2010-2013 में यह 15 प्रतिशत से 28 प्रतिशत रही थी। जैसा कि इस समीक्षा के खंड-2 के अध्याय-1, भाग-2 में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, दुर्बलतापूर्ण साख वृद्धि ने आर्थिक विकास को प्रभावित किया है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिए पीएसबी द्वारा अपनी पूरी क्षमता से निष्पादन करने और ऋण देना बंद करने के बजाय आर्थिक विकास का समर्थन करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऋण देना बंद का संवृद्धि और कल्याण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।

चित्र 5: बैंक ऋण वृद्धि (प्रतिशत)

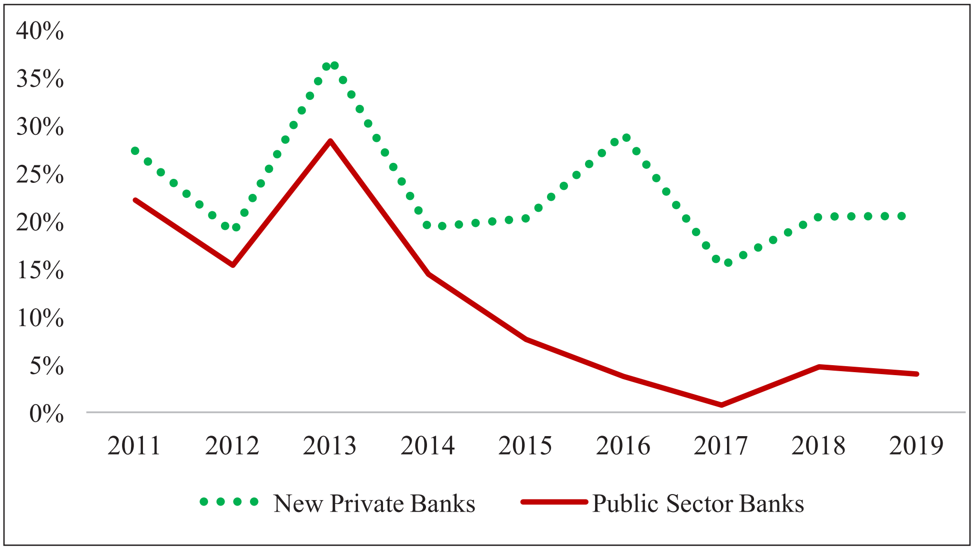

स्रोतः आरबीआई डाटा व समीक्षा परिकलन

7.5 ऐतिहासिक रूप से पिछले 50 वर्षों में, शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं को हमेशा उनके बैंकों द्वारा पूरी तरह से समर्थन/सहयोग प्रदान किया गया है। अमेरिका को आर्थिक महाशिक्ति बनाने में अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली का सहयोग अच्छी तरह से प्रलेखित है। इसी प्रकार अस्सी के दशक में, जापानी अर्थव्यवस्था की समृद्धि के उत्कर्ष के दौरान तत्कालीन सबसे बड़े 25 बैंकों में जापान के 15 बैंक आते थे। हाल के दिनों में, चीन एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा है, इसे अपने बैंकों द्वारा समर्थन दिया गया है–वैश्विक रूप से शीर्ष चार सबसे बड़े बैंक, चीनी बैंक ही हैं। विश्व का सबसे बड़ा बैंक, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना (चीन का औद्योगिक और व्यावसायिक बैंक), चौथे या पांचवे बृहत् बैंक से लगभग दो गुना बड़ा है, जो क्रमश: जापानी और अमेरिकी बैंक हैं। उपर्युक्त संबंध का उपयोग करते हुए हम अनुमान लगाते हैं कि यदि भारतीय बैंक भी भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुपात में बड़े हों तो विश्व के 100 शीर्ष बैंकों में कम से कम छ: बैंक हमारे होने चाहिए। इसी तरह, 5 ट्रिलियन इकॉनमी/अर्थव्यवस्था बनने वाले भारत को विश्व स्तर पर शीर्ष 100 में शामिल हा सकने वाले कम से कम 8 भारतीय बैंकों की आवश्यकता होगी। इसलिए, भारत में बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

7.6 चूंकि भारतीय बैंकिंग से बाजार हिस्सेदारी का 70 प्रतिशत पीएसबी के पास है, अत: भारतीय अर्थव्यवस्था का समर्थन/सहयोग करने और इसके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का दायित्व भी उन्हीं का बनता है। हालांकि वर्ष-2019 में पीएसबी की सामूहिक हानि मुख्यत: अशोध्य ऋण की वजह से ₹ 66,000 करोड़ से अधिक है जो कि एक ऐसी राशि है जो शिक्षा के लिए देश के बजटीय आवंटन को लगभग दोगुना कर सकती है। बैंक धोखाधड़ी के 85 प्रतिशत प्रतिवेदित मामले पीएसबी के कारण ही हैं जबकि उनकी सकल अनर्जक परिसंपत्तियां (एनपीए) 7.4 लाख करोड़ की हैं जो वर्ष 2019 के कुल अवसंरचना व्यय के 150 प्रतिशत से अधिक है। पूंजी पर प्रतिप्राप्ति का 2019 का अनुपात स्पष्ट करता है कि पीसीबी में सरकार द्वारा निवेशित प्रत्येक रूपये में 23 पैसे का क्षरण हो रहा है। बाजार और खाता मूल्यांकनों का अनुपात, जो बैंक के प्रशासन की गुणवत्ता को दर्शाता है, 20 जनवरी, 2020 को पीएसबी के लिए 0.8 रहा जबकि एनपीबी मे यह 4 था। पीएसबी को दत्त बनाने और इस प्रकार आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देने योग्य बनाने के लिए संरचनात्मक समाधान अनिवार्य हो गए हैं।

7.7 लगभग 4,30,000 करोड़ करदाताओं का धन सरकारी पूंजी के रूप में पीएसबी में निवेश किया हुआ है। वर्ष 2019 में पीएसबी में निवेश किये गये करदाताओं के प्रत्येक रूपये में से औसतन 23 पैसे की हानि हुई। इसके विपरीत 1991 में भारत में उदारीकरण के बाद लाइसेंस दिए गए ''नए प्राइवेट बैंकों (एनपीबी) में निवेश किए गए प्रत्येक रूप में 9.6 प्रतिशत लाभ हुआ। चूंकि पीएसबी और एनपीबी एक ही घरेलू बाजार में परिचालित होते हैं, इसलिए पीएसबी की कार्यकुशलता बढ़ाने की आवश्यकता है।

7.8 पीएसबी में कार्यक्षमता में कमी के स्तर को समझने के लिए हम पीएसबी में करदाता के निवेश पर प्रतिफल में परिवर्तन से संभावी लाभ का अनुमान लगा रहे हैं। एक औसत एनपीबी में किसी निवेशक द्वारा अर्जित प्रतिफल उस बेंचमार्क का प्रतिनिधित्व करता है जिसका उपयोग करदाता द्वारा पीएसबी में उसके निवेश पर हुई हानि का अनुमान लगाने के लिए किया जाना चाहिए। चित्र 6 दर्शाता है कि इस बेंचमार्क का प्रयोग कर पीएसबी में करदाता के निवेश पर पूवामानित घाटा सबसे बड़ी सब्सिडी अर्थात् 1.4 लाख करोड़ की राशि से अधिक की खाद्य सब्सिडी के लिए दी गई राशि से तुलनीय है।

7.9 कार्यकुशलता में कमी के पैमाने को समझने के लिए दूसरा तरीका निम्नलिखित प्रश्न पूछना है: पीएसबी में निवेश से करदाता कुल कितना मूल्य प्राप्त करता है? इस प्रयोजन से हम प्राइवेट सेक्टर के नए बैंकों (एनपीएसबी) की तुलना में स्टॉक मार्केट से पीसबी के बही मूल्य के अनुपात का प्रयोग करते हैं। 20 जनवरी, 2020 को हम पाते हैं कि करदाताओं के धन का प्रत्येक रूपया 71 पैसे का बाजार मूल्य लाता है। इसकी तुलना में एनपीबी में निवेश किये गये प्रत्येक रुपये से 3.70 का बाजार मूल्य प्राप्त होता है अर्थात पीएसवी में निवेश किए गए रुपये के मूल्य से पांच गुना। इससे स्वाभाविक प्रश्न उठता है। यदि प्रत्येक पीएसबी के बाजार से बही अनुपात दोगुना हो पाए, जिसमें अत्यधिक सामान्य स्पष्ट वृद्धि की परिकल्पना की गई है, क्योंकि औसत पीएसबी तब भी एनपीबी द्वारा औसतन पैदा करने वाले मूल्य के

एक तिहाई मूल्य ही पैदा करेगा। चित्र 7 दर्शाता है कि लाभ 5.2 लाख करोड़ रुपए होगा। यह राशि वर्ष 2019 के लिए विनिवेश हेतु बजट में प्रावधान की गई राशि से पांच गुना है और यथार्थपरक पर बहुत ही कम परिदृश्य यह अनुमान लगाना होगा कि प्रत्येक पीएसबी का बाजार से बही अनुपात दूसरे निकृष्टतम निष्पादक एनपीबी के समकक्ष तो हो जाए। यह यथार्थपरक परिदृश्य है क्योंकि सबसे खराब निष्पादन करने वाले एनपीबी का बाजार से बही अनुपात पीएसबी के लिए माध्य से अधिक है। इस प्रकार, यहां हमारा अनुमान है कि प्रत्येक पीएसबी में करदाता का निवेश कम से कम निम्नतम एनपीबी के बाजार से वही अनुपात के समकक्ष तो होगा। इस परिवर्तन से सरकार को 9.1 लाख करोड़ रु का लाभ होगा जो वर्ष 2019 के लिए विनिवेश में किए गए बजट अनुमान से लगभग 8.5 गुना अधिक है। प्रत्येक पीएसबी के बाजार से बही अनुपात में परिवर्तन कर एनपीबी के माध्य के बराबर करने पर सरकार को 10.2 लाख करोड़ की प्राप्ति होगी, जो वर्ष 2019 के लिए निवेश के लक्ष्य से नौगुना है। अंत में, प्रत्येक पीएसबी के बाजार से बही अनुपात में एनपीबी के माध्य से सरकार को 11.8 लाख करोड़ लाभ होगा, जो वर्ष 2019 के लिए विनिवेश से 11 गुना है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, पीएसबी और एनपीबी में प्राथमिक अंतर कार्यकुशलता में अंतर और उससे उत्पन्न होने वाले अंतरों से आस्तित्व में आता है। इस दृश्य विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि पीएसबी की कार्यक्षमता में कमी से उत्पन्न होने वाली लागतें बहुत अधिक हैं।

चित्र 6: पीएसबी में निवेश से करदाता की धनराशि की हानि की बड़ी सब्सिडी मदों से तुलना (2019)

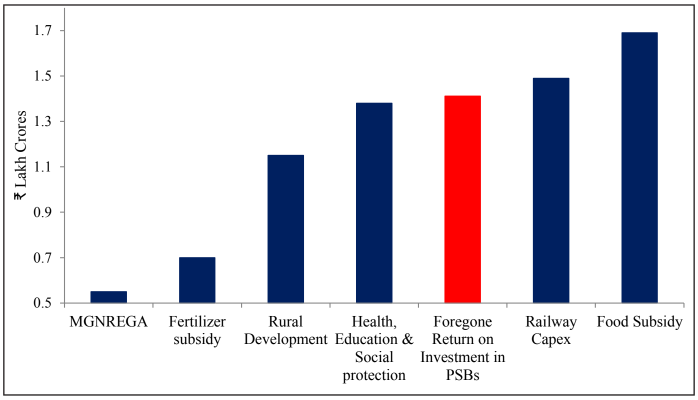

स्रोत: बजट दस्तावेज, आरबीआई बुलेटिन और समीक्षा आंकलन

चित्र 7: पीएसबी में दक्षता वृद्धि से करदाता को संभावी लाभ

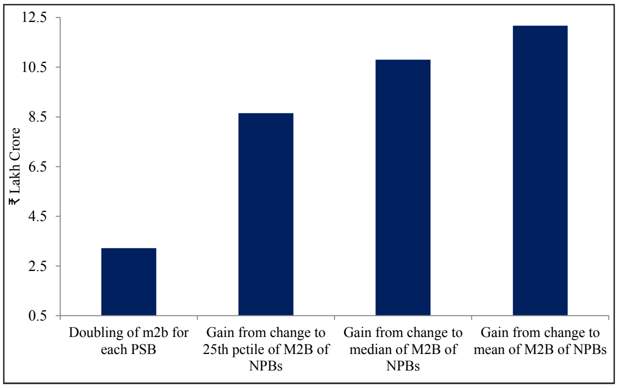

स्रोत 7: समीक्षा परिकलन

टिप्पणी: एम2बी अनुसूचित बैंक का बाजार और वही मूल्य अनुपात दर्शाता है

7.10 भारत को यह पहचानने की आवश्यकता है कि सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति बड़े पैमाने पर अन्य वित्तीय मध्यस्थता मॉडलों का उपयोग करते हुए की जा सकती है। व्यष्टिवित्त (माइक्रो फाइनेंस) के घातांकीय वृद्धि और इसके प्रभाव ने इस बिन्दु को विशेषरूप से दर्शाया है (बॉक्स 1 को देखें)। इसके अलावा, जैसे कि बाद में स्पष्ट किया गया है, अन्य व्यावसायिक मॉडलों - एम पी बी या व्यष्टिवित्त (माइक्रो फाइनेंस) संस्थाओं (एम एफ आई) की कुछ कमजोरियों को रेखांकित करते हुए जिस प्रकार पी एस बी की यथास्थिति बनाए रखने का समर्थन किया जाता है, वह दो विषम चीजों की तुलना करते हुए निष्कर्ष देने के समान है। किसी भी आर्थिक क्रियाकलाप में निष्पादन में विषमता का होना अनिवार्य है। चूंकि पी एस बी निष्पादन में काफी भिन्नता है, कुछ पी एस बी अन्य की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, ठीक उसी प्रकार एनपीबी और एमएफआई के प्रदर्शन में भी कुछ भिन्नता होनी चाहिए। हालांकि, औसत प्रदर्शन करने वाले पी एस बी की तुलना सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले एन पी बी/एम एफ आई के साथ करना गलत है, क्योंकि इसमें दो सांख्यिकीय उपायों - औसत और बेहतर कार्य-निष्पादन - का मिश्रण कर दिया जाता है, जो कि अंततः दो विषम चीजों की तुलना करते हुए निष्कर्ष देने के समान है। संक्षेप में, यह पीएसबी में कार्यनिष्पत्ति में सुधार करने से अत्यंत आवश्यक है।

7.11 भारत (i) एक सकारात्मक जनसांख्यिकीय लाभांश; (ii) लगभग 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन वाली जैम ''ट्रिनिटी'' द्वारा समर्थित आधुनिक डिजिटल अवसंरचना जिसमें बायोमेट्रिक्स-आधारित विशिष्ट पहचान प्रणाली और मोबाइल नेटवर्क संरचना भी है और (पपप) एक समान नए सिरे से बनाया गया जी एस टी नेटवर्क जो कि सम्पूर्ण भारत में इलेक्ट्रॉनिक अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली है, के कारण विभिन्न कारकों के विशिष्ट सह प्रवाह के कारण अपने संवृद्धि-पथ के महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। ये निवेश आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए एक मंच प्रदान करते हैं जिसमें दस करोड़ लोग एवं व्यवसाय का औपचारिक वित्तीय प्रणाली में समावेश हो रहा है।

7.12 भारत की वर्तमान जनसांख्यिकी और संवृद्धि अवसरों को ध्यान में रखते हुए अब हमें एक उन्नतिशील बैंकिंग क्षेत्र की आवश्यकता है। एक उद्यमी बैंकिंग प्रणाली ही वह सहयोग कर सकती है और गुणात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकती है तथा भारत के संवृद्धि पथ को एक सकारात्मक दिशा में स्थायी रूप से ले जा सकती है। इसके विपरीत, अदक्ष पीएसबी, उन विशेष अवसरों का विदोहन करने की देश की क्षमता को गंभीर क्षति पहुंचा सकते हैं, जिन्हें वह आज उपयोग में ला सकता है। ऐसी परिणति होने पर देश की आर्थिक संवृद्धि पीढ़ियों पीछे जा सकती है। जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है एक दक्ष बैंकिंग व्यवस्था की सहायता के बिना कोई भी देश प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्था नहीं रह पाया है। जहां तक एक 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के अपने लक्ष्य की दिशा में भारत की यात्रा का संबंध है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, जोकि हमारी बैंकिंग प्रणाली में प्रभाविता रखते हैं, को और दक्ष होना जरूरी है।

बॉक्स 1 सामाजिक प्रभाव हेतु निजी क्षेत्र में वित्तीय मध्यस्थता: व्यष्टि वित्त (माइक्रो फाइनेंस) का केस

व्यष्टि वित्त क्षेत्र, विशेष रूप से वर्ष 2000 से इसके कायाकल्प को देखते हुए, पीएसबी के व्यावसायिक मॉडलों से भिन्न मॉडलों के उपयोग के स्तर पर सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। अधिकांश व्यष्टि वित्त (एमएफआई) ने अलाभार्थी संस्थाओं के रूप में अपनी शुरूआत की है। वर्ष 2000 के बाद, यद्यपि एमएफआई का उद्देश्य यही बना रहा कि समावेशी विकास और वित्तीय समावेशन के माध्यम से गरीबी उन्मूलन किया जाए तथापि साथ-ही-साथ इन्होंने सामाजिक लक्ष्य के अनुसरण के विशुद्ध लक्ष्य से होकर, सामाजिक और वित्तीय लाभ प्राप्त करने की दोहरी अंतर्निहित संकल्पना का अनुसरण प्रारंभ कर दिया है। कुछ अग्रणी एमएफआई संस्थाओं द्वारा अर्जित उत्तम वित्तीय प्रतिलाभों के साथ 'सबसे निचले स्तर' पर सामाजिक प्रभाव डालने पर फोकस से, इस क्षेत्र में मुख्यधारा की अनेक वाणिज्यिक संस्थााओं का प्रवेश हुआ। उदाहरण के लिए, कुछ बैंक इस वर्ग के लिए आगे और धन उधार देने के लिए एमएफआई को ऋण देते हुए इनके साथ साझेदारी करते हैं और इनकी प्राथमिकता वाली ऋण देनदारियों को पूरा करते हैं। वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र की व्यष्टि वित्त (माइक्रो फाइनेंस) घोषणा में गरीबी उन्मूलन के संबंध में एमएफआई संस्थाओं की भूमिका को रेखांकित किया गया। कुछ एमएफआई ने स्वयं को बैंकों के रूप में परिवर्तित भी कर लिया है। चित्र क में, वर्ष 2000 से एमएफआई के प्रभाव में होने वाली घातांकी वृद्धि को दर्शाया गया है। वर्ष 2016 की स्थिति के अनुसार, 97 प्रतिशत ऋण धारक महिलाएं थीं औरं लगभग 30 प्रतिशत ऋण धारक अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग से और 29 प्रतिशत अल्पसंख्यक वर्ग से थे। यह दर्शाता है कि इन एमएफआई द्वारा दिये जाने वाला ऋण प्राथमिक तौर पर समाज के सीमांत वर्गों की जरूरतों को पूरा करता है।

चित्र कः ग्राहकों तक एमएफआई की पहुंच में घातांकी वृद्धि

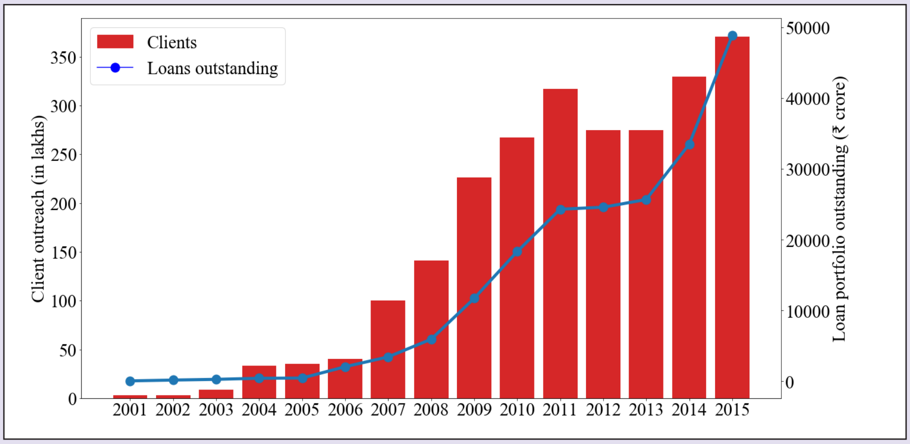

स्रोतः भारत माइक्रो फाइनेंस रिपोर्ट 2012 और 2015

बैंकिंग संरचनाः राष्ट्रीयकरण से अब तक

7.13 भारत में बैंकिंग हजारों वर्षों से चली आ रही है। वैदिक काल में भारत के कई प्राचीन ग्रंथों में बैंक ऋण कार्यों का उल्लेख है। भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की जड़ें 1800 के दशक से शुरू होने वाले औपनिवेशिक युग में हैं। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) अनिवार्य रूप से औपनिवेशिक काल से चले आ रहे विरासत वाले बैंक हैं, जिनका बाद में राष्ट्रीयकरण किया गया। उदाहरण के लिए, भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, जो वर्तमान में विश्व स्तर पर 55वां सबसे बड़ा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की स्थापना 1806 में बैंक ऑफ कलकता के रूप में की गई थी, 1921 में इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया और 1955 में यह राज्य के स्वामित्व के अधीन आ गया। शेष भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का गठन राष्ट्रीयकरण की दो लहरों, 1964 और 1980 के बाद हुआ। 1980 के राष्ट्रीयकरण के बाद, राष्ट्रीय बैंकिंग बाजार में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का शेयर 91 प्रतिशत है, जबकि शेष 9 प्रतिशत उन ''पुराने निजी बैंकों'' (ओपीबी) का है, जिनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था।

7.14 1969 के राष्ट्रीयकरण के बाद के 50 वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र की बाजार संरचनाविकसित हुई है। मार्च, 2019 तक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास जमा राशि में 80 लाख करोड़ थी, सरकारी बांड में 20 लाख करोड़ थे, और उनके द्वारा 58 लाख करोड़ का ऋण और अग्रिम प्रदान किया गया, जो इस बात को दर्शाता है कि यह भारत में परिचालित समस्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल राशि का 65 प्रतिशत और 70 प्रतिशत के बीच की राशि है।[2] उनके पास सरकारी ऋण का लगभग 20 लाख करोड़ रुपये है, इसका एक बड़ा हिस्सा न्यूनतम ''सांविधिक चलनिधि'' अनुपात की आवश्यकताओं से संबंधित है। इस प्रकार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की आज बाजार में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी तो है ही, इसके साथ इनका महत्वपूर्ण पदचिन्ह भी मौजूद है, जो 1980 के राष्ट्रीयकरण के बाद 91 प्रतिशत से कुछ कम हो गया है। बाजार में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शेयर में गिरावट का मुख्य कारण उन ''नए निजी बैंकों'' (एनपीबी) का आगमन रहा है, जिन्हें 1990 के दशक की शुरुआत में लाइसेंस प्रदान करने के नियमों, के उदारीकरण के बाद, लाइसेंस प्रदान किए गए थे।

7.15 पीएसबीएस, ओपीबीएस और एनपीबीएस वर्तमान में अपने समस्त कामकाज, जिसमें शाखा निर्माण और ऋण देने संबंधी प्राथमिक कार्य-क्षेत्र शामिल है, के लिए समान बैंकिंग नियमों के अधीन हैं। राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और निजी बैंकों के बीच

[2] समग्र बैंकिंग आंकड़े आरबीआई द्वारा अनुरक्षित भारतीय अर्थव्यवस्था पर डाटाबेस से लिये गए है। https://dbie.rbi.org.in/ देखें

मुख्य अंतर यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अधिकांशतः सरकार के स्वामित्व के कारण अपेक्षाकृत कम रणनीतिक और परिचालन संबंधी स्वतंत्रता का आनंद ले पाते हैं। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समस्त कार्यों पर महत्वपूर्ण नियंत्रण रखती है, जिसमें भर्ती से संबंधित नीति से लेकर निवेश एवं वित्तपोषण को भुगतान करने और बोर्ड एवं शीर्ष प्रबंधन की नियुक्ति सहित बैंक प्रशासन पर नियंत्रण रखना भी शामिल है। सरकार के अधिकांश मालिकाना हक और बैंक की कार्यप्रणाली पर इसके परमादेश के कारण ही बैंक की देयता के बेलआउट पर सरकारी अंतर्निहित वचनबद्धता रहती है, जिसके कारण करदाताओं पर एक अंतर्निहित बोझ पड़ता है। सरकार के अधिकांश स्वामित्व के कारण भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों के निर्णय केंद्रीय सतर्कता आयोग और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के जांच के अधीन होते हैं। इस बात के प्रतिबंध के बिना कि किस परिस्थिति में, क्या जांच की जाए, सतर्कता जांच के आवरण में उत्पीड़न की आशंकाओं के कारण सरकार द्वारा संचालित बैंकों के अधिकारी ऋण देने या अशोध्य ऋण की वार्ता में जोखिम लेने से सावधान रहते हैं।

राष्ट्रीयकरण के लाभ

7.16 राष्ट्रीयकरण से क्या लाभ हुआ? बैंकिंग संसाधनों की ग्रामीण क्षेत्रों, कृषि और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आवंटन बढ़ी है। 1969 के राष्ट्रीयकरण बाद से पहले दशक में कुछ कच्चे आंकड़ों पर विचार करें। ग्रामीण बैंक शाखाओं की संख्या, 1969 में लगभग 1,443 से 1980 में 15,105 शाखाओं के साथ दस गुणा वृद्धि हुई। शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 5,248 से 13,300 शाखाएं यानि दो गुना वृद्धि रही। ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट बीस गुणा वृद्धि के साथ 115 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,000 करोड़ रुपए हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में जमा राशि 306 करोड़ रुपए से बढ़कर 5,939 करोड़ रुपए हो गई, यह भी 20 गुना वृद्धि हुई। 1969 और 1980 के बीच कृषि का ऋण चालीस गुणा बढ़कर 167 करोड़ से 2,767 करोड़ हो गया, जो जीडीपी के 2 प्रतिशत के शुरूआती बिंदु से 13 प्रतिशत तक पहुंच गया। यह घटनाक्रम इस बात को दर्शाता है कि किसानों को ऋण की कम आपूर्ति की समस्या में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, राष्ट्रीयकरण के कारण इसमें गति आई है। ग्रामीण बैंक जमा राशि संग्रहण और ग्रामीण ऋण दोनों में 1969 के राष्ट्रीयकरण के बाद काफी वृद्धि हुई है।

7.17 हालांकि, उपरोक्त प्रवृत्तियों की व्याख्या में यह सावधानी बरतना आवश्यक है कि राष्ट्रीयकरण ही उपरोक्त प्रवृत्तियों के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी नहीं है। इस तरह की व्याख्या में एक मुख्य सहवर्ती घटक अन्य दखलों की भूमिका भी है। उदाहरण के लिए, सरकार ने 1969 और 1977 के बीच एक "हरित क्रांति" शुरू की। इसके अलावा, कई गरीबी-निरोधी कार्यक्रम भारत की चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं में चिन्हित रहे हैं जो इसके राष्ट्रीकरण पर आश्रित रहे हैं। राष्ट्रीयकरण के बाद आरबीआई द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण सहवर्ती प्रभाव प्रारंभ हो गए। इसके निर्देशित उधार कार्यक्रमों के अधीन मूल्य निर्धारण फार्मूला, जिसके माध्यम से बाजारों की अर्थव्यवस्थाओं के बजाय केंद्रीय योजना के आधार पर ऋण पर बैंकों द्वारा वसूल किए जाने वाले ब्याज की दरों को निर्धारित की जाती है, के एक जटिल मिश्रण का उपयोग करके प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आरबीआई ने अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करने हेतु औपचारिक साधन और नैतिक प्रोत्साहन का उपयोग किया। इस बात को देखते हुए कि बैंक अनिवार्य रूप से एक बंद बाजार व्यवस्था में परिचालित थे, यह स्पष्ट है कि इन कारकों ने इसे विशेष बल प्रदान किया है।

बॉक्स 2: राष्ट्रीयकरण के प्रभाव पर साक्ष्य आधारित अनुसंधान

राष्ट्रीयकरण्या से किस चीज़ की प्राप्ति हुई है उसके बारे में निष्कर्ष से इस बात की प्रतितथ्यात्मक स्थिति पर विचार करना चाहिए कि किस चीज़ की प्राप्ति की जा सकती है और कया किसी भी प्रकार का राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए था। इस प्रतितथ्यात्मकता का उपयोग करके राष्ट्रीयकरण के लाभ केवल आंकलन ही किया जा सकता है। कुछ ऐसे चिंताशील अध्ययन रहे हैं, जिनसे इस चिंताशील शीशे का प्रयोग करके बैंक के राष्ट्रीयकरण के प्रभाव का पर्यवेक्षण किया गया है। ये नतीजे मिश्रित हैं।

बर्गेस और पांडे (2005) में आर.बी.आई के 4:1 सूत्र का अध्ययन किया गयाहै जहां किसी बैंक के लिए वर्ष 1977 और 1991 के बीच एक शहरी शाखा खोलने के लिए लाइसेंस लेने के लिए 4 ग्रामीण शाखाएं खोलना अपेक्षित

था। उन्होंने यह पाया कि यह नीति वित्तीय रूप से कम विकसित राज्यों में गरीबी में महत्वपूर्ण कमी का कारण रही है। हालांकि कोचर)2005) ने यह तर्क दिया है कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.), जो कि सरकार का एक सर्वोत्कृष्ट गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, उसे वित्तीय रूप से कम विकसित राज्यों में अतयधिक गहनता से इस अवधि के दौरान तत्परता से कार्यान्वित किया गया था। अत: यह निष्कर्ष निकालना प्राय: असम्भव है कि सरकारी बैंक की शाखा में विस्तार गरीबी में कमी आने का कारण रहा है। यह तर्क देते हुए कि यहां तक कि राष्ट्रीयकरण से पहले समान तीव्रता (गहनता) वाला शाखा विस्तार कार्यक्रम मौजूद था, पनगढ़िया (2006) ने भी बर्गेस और पांडे (2005) में मौजूद नतीजों को असवीकृत किया था, और इसीलिए शाखा विस्तार के संबंध में 1977-1991 की अवधि विशेष नहीं है। अन्य शब्दों में, 1977-1991 के दौरान देखा गया गरीबी पर विभेदक प्रभाव राष्ट्रीयकरण का कारण नहीं हो सकता है। अंतत:, कोले (2007) ने वर्ष 1980 में आरंभ किए गए बैंक राष्ट्रीयकरण के दूसरे तरंग के प्रभाव का सावधानी से जांच की। कतिपय शुरुआती आकार वाले उक्त बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था उन्होंने इस तथ्य का लाभ उठाते हुए जो बैंक राष्ट्रीयकरण दहलीज (द्वार) को सीमांत तौर पर पार किया है, उन उच्चतर अनुपात वाले बैंक के क्षेत्रों का जो बैंक अत्यंत कठिनाई से इस दहलीज को पार करने से चूक गए हैं, उन उच्चतर अनुपात वाले बैंकों के क्षेत्र की तुलना किया है। इस अध्ययन से वास्तविक अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीयकरण के किसी भी महत्वपूर्ण लाभ का पता नहीं चलता। वस्तुत: उन्होंने यह दर्शाया है कि व्यापार और सेवा में रोज़गार में कमी आई है और वित्तीय मध्यस्थता बिगड़ गई है। केवल क्रेडिट की गुणवत्ता में ही वृद्धि हुई थी।

इन अध्ययनों से परे, हमें यह भी ज्ञात है कि राष्ट्रीयकरण के बावजूद 2014 तक गरीबों का एक बड़ा हिस्सा बड़ा हिस्सा बैंकों से वंचित था। बड़े हिस्से में, वित्तीय समावेश अगस्त 2014 में प्रधान मंत्री जन धन योजना (पी. एम. जे. डी. वाई.) के माध्यम से हुआ था, जिसके पहले सप्ताह में 18 मिलियन से अधिक बैंक के खाते खोले गए थे, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिर्कार्ड्स में एक रिर्कार्ड है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कमजोर होना

7.18 पी एस बी से संबंधित 2019 निष्पादन के आंकड़े संयत करने वाले हैं। 2019 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने सकल और निवल एन पी ए क्रमश: 7.4 लाख करोड़ और 4.4 लाख करोड़ दर्ज किए जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली का लगभग 80 प्रतिशत है। पी एस बी के सकल एन पी ए उनके सकल अग्रिम का 11.59 प्रतिशत रहे, यद्यपि थोड़ा बहुत उत्साहवर्धक प्रवृत्ति यह रही कि एन पी ए अनुपात 2018 के 14.58 प्रतिशत अनुपात से कम रहा जिसने यह आशा जगाई कि गैर-निष्पादन परिसंपदा समस्या अपने शीर्ष तक पहुंच चुकी है और यह अब नीचे आ रही है। इसके अतिरिक्त, 2019 में, पी एस बी ने अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के 421 बिलियन के लाभों अथवा एन पी बी के 390 बिलियन लाभों की तुलना में 661 बिलियन की हानि वहन की। एन पी से होने वाली हानियों के साथ-साथ, कपट भी पी एस बी की चिंता का एक और विषय है। भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणी से पता चलता है कि 2017-2018[3] में रिपोर्ट किए गए कपट के 5835 मामलों में से 92.9 प्रतिशत और लगभग 41,000 करोड़ की कपट राशि में से 85 प्रतिशत पी एस बी की हैं। विगत में पी एस बी की उपलब्ध्यिों के बावजूद भी, जैसा इस अध्याय में पहले काफी बताया जा चुका है, पी एस बी आज स्पष्टत: कार्यक्षम नहीं है।

औसत की तुलना करना

7.19 सामयिक रुझान, जो पी एस बी और एन पी बी की ''अंतर-में-अंतर'' से तुलना करता है उससे पता चलता है कि पी एस बी की कमजोरियां अचानक विकसित नहीं हुईं। चित्र 8 2005 से 2019 के बीच पी एस बी और एन पी बी के लिए परिसंपदाओं पर प्रतिलाभ (आर.ओ.ए.) उल्लिखित करती है। जहां 2009 से पहले पी एस बी और एन पी बी की एक समान आर ओ ए हुआ करती थी, वहीं 2009 में पी एस बी की आर ओ ए ने गिरना आरंभ कर दिया तथा 2019 तक यह गिरती ही रही। एन पी बी की आर ओ ए 2013 तक बढ़ती रही, तत्पश्चात गिरने लगी, जो 2013 से सभी बैंकों में एक समान प्रवृत्ति ही परिलक्षित करता है। यद्यपि, पी एस बी की आर ओ ए कहीं अधिक तीव्र गति से गिरी है।

[3] 29 अगस्त, 2018 को जारी आर बी आई की वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय VI से लिए गए आंकड़े, प्राप्त किए जा सकते हैं https://rbi.org.in/Scripts/AnnualReportPublications.aspx?Id=1233

7.20 चित्र 9 इक्विटी पर प्रतिलाभ (आर ओ ई) में इसी प्रकार की प्रवृत्ति दर्शाता है। चित्र 10 और 11 सकल अग्रिम पर सकल और निवल एन पी ए के अनुपात को दर्शाता है। दोनों अनुपात 2010 के बाद पी एस बी के लिए काफी तेज़ी से बढ़ते चले गए परंतु एन पी बी के लिए यह वृद्धि हाल ही तक कम तीव्र अथवा यहां तक कि सपाट भी रही। चित्र 10 और 11 स्पष्टत: संकेत देते हैं कि विगत कुछ वर्षों में विकसित परिसंपदा गुणता समस्या पी एस बी के निष्पादन की गिरावट का कारण है। चित्र 12 दो प्रकार के बैंकों के कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात प्रदर्शित करता है जबकि चित्र 13 कोर 'टियर 1' पूंजी अनुपात प्रदर्शित करता है। ये अनुपात दर्शाते हैं कि बैंक की हानियों ने पीएसबी के पूंजी आधारो को उनके निजी सह-संगणकों की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचाया है।

7.21 पीएसबी की एनपीए समस्याओं की एक संभाव्य व्याख्या यह है कि वर्ष 2004 और 2011 के बीच भारतीय अर्थ-व्यवस्था की वृद्धि के चरण में पीएसबी ने अपने ऋण संविभाग (पोर्ट फोलियो) को तो विकसित किया परंतु यह ऋण वृद्धि संदिग्ध गुणता की थी। जब अर्थव्यवस्था की गति धीमी हुई, तो बैंकिंग प्रणाली में एनपीए में आकस्मिक वृद्धि हुई।

चित्र 8: बैंकों की परिसंपदाओं पर परिलाभ (प्रतिशत)

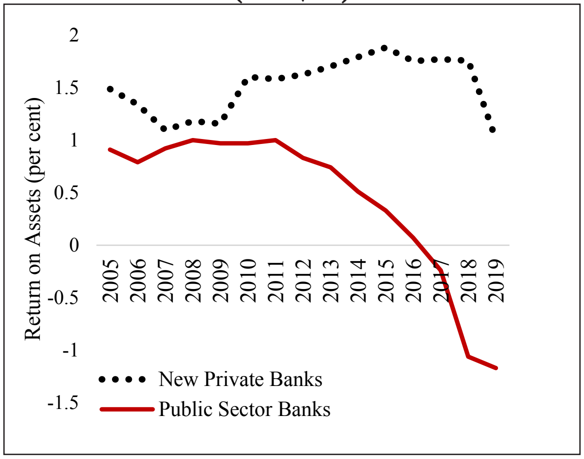

स्रोत: आरबीआई आकड़े और समीक्षा परिकलन

चित्र 9: बैंकों की इक्विटि पर परिलाभ (प्रतिशत)

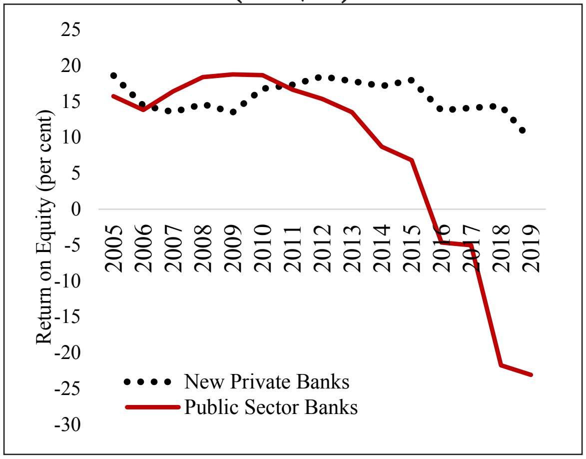

स्रोत: आरबीआई आकड़े और समीक्षा परिकलन

चित्र 10 सकल गैर-निष्पादन परिसंपदा अनुपात (प्रतिशत) अग्रिम

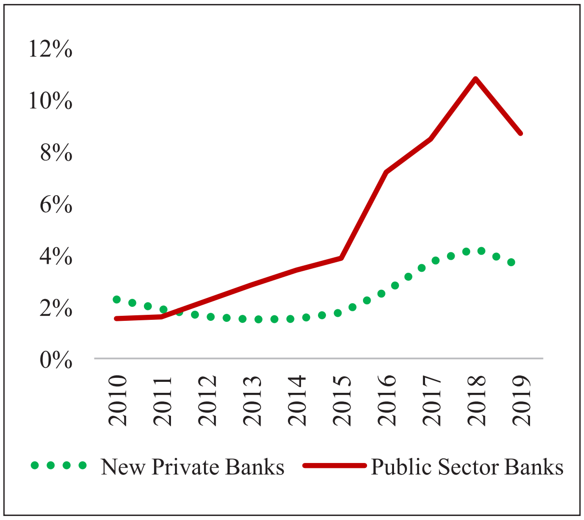

स्रोत: आरबीआई आकड़े और समीक्षा परिकलन

चित्र 11: निवल गैर-निष्पादन परिसंपदा अनुपात (प्रतिशत) अग्रिम

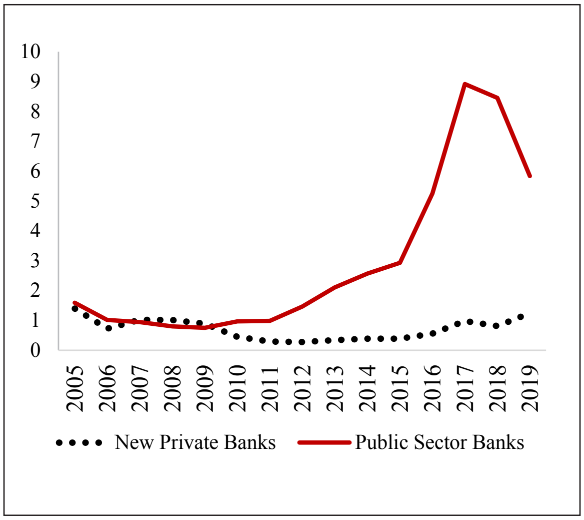

स्रोत: आरबीआई आकड़े और समीक्षा परिकलन

चित्र 12 कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात (प्रतिशत)

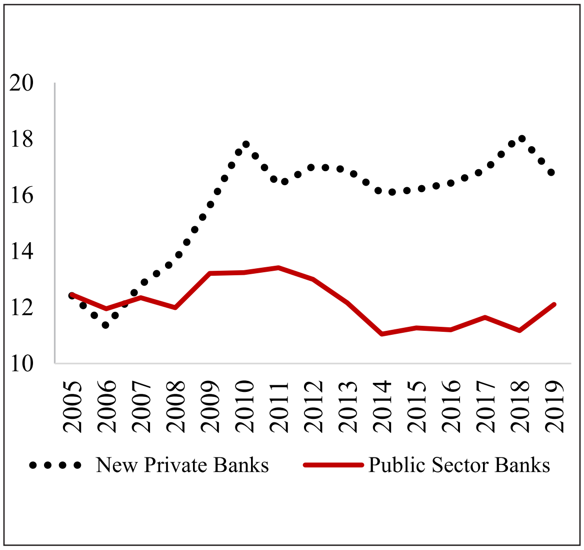

स्रोतः आरबीआई आकड़े और समीक्षा परिकलन

चित्र 13 स्तर-1 पूंजीगत पर्याप्तता अनुपात (प्रतिशत)

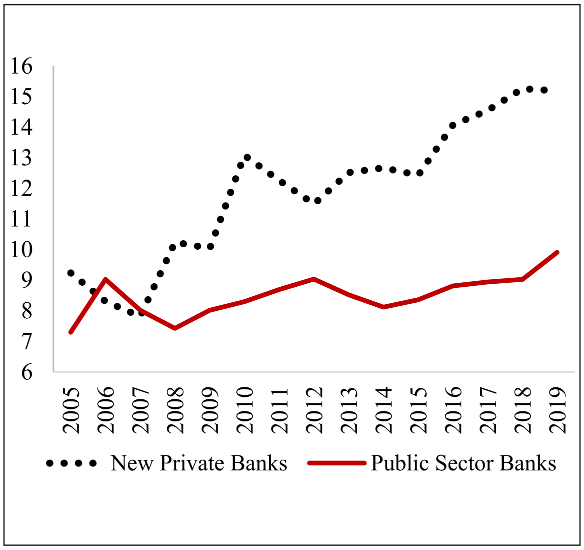

स्रोतः आरबीआई आकड़े और समीक्षा परिकलन

7.22 चित्र 14कः इस तथ्य को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि धनराशि के आधार पर बैंक धोखाधड़ी के 90 प्रतिशत से अधिक मामले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हुए। धोखाधड़ी के कुल मामलों में निजी बैंकों का अंश 8 प्रतिशत से कम है। इन धोखाधड़ी मामलों का बड़ा हिस्सा (90.2 प्रतिशत) अग्रिम राशियों से संबंधित है (चित्र 14ख)। चक्रवर्ती (2013) इस बात पर प्रकाश डालता है कि अग्रिम के लगभग 90 प्रतिशत मामलों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि होती है। इसलिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अंगीकृत ऋणनीति में स्क्रीनिंग और मानिटरन प्रक्रिया की गुणवत्ता पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

चित्र 14: बैंकों में धोखाधड़ी (प्रतिशत)

क. अंतर्निहित राशि के आधार पर धोखाधड़ी की समूह-वार संक्षिप्त जानकारी

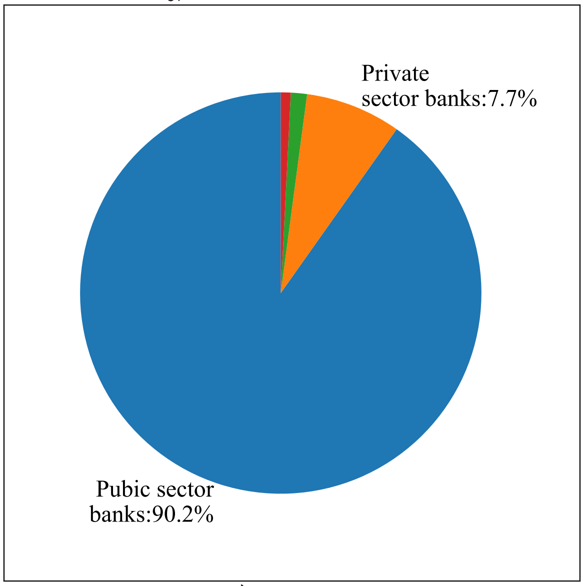

ख. अंतर्निहित राशि के आधार पर धोखाधड़ी मामलों की प्रचालन-वार संक्षिप्त जानकारी

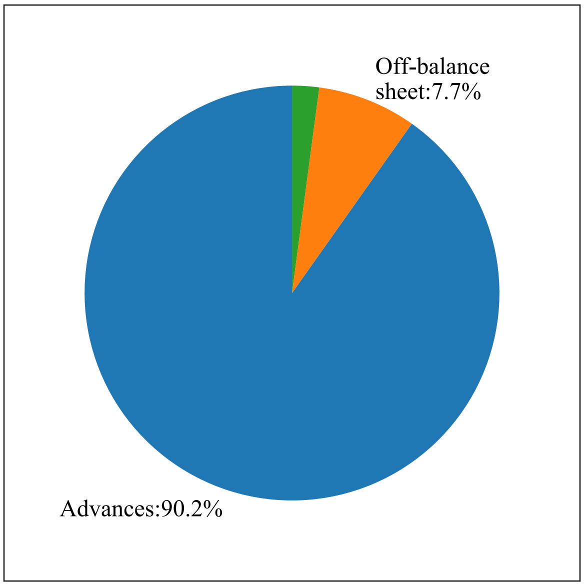

स्रोतः आरबीआई आकड़े और समीक्षा परिकलन

7.23 मैट्रिक्स की श्रृंखला में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का खराब प्रदर्शन उनके इक्विटी मूल्यों में भी परिलक्षित होता है। चित्र 15 में दो प्रकार के बैंकों के लिए इक्विटी के बुक किए गए मूल्य के मुकाबले इक्विटी के बाजार मूल्य के अनुपात को दर्शाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का औसत बाजार से बही अनुपात 0.64 के तुल्य है, जो एन पी बी के लिए 3.33 की माध्यिका 1/5 से भी कम होता है।

चित्र 15: बैंकों के मार्केट-टू-मार्किट अनुपात का संवितरण

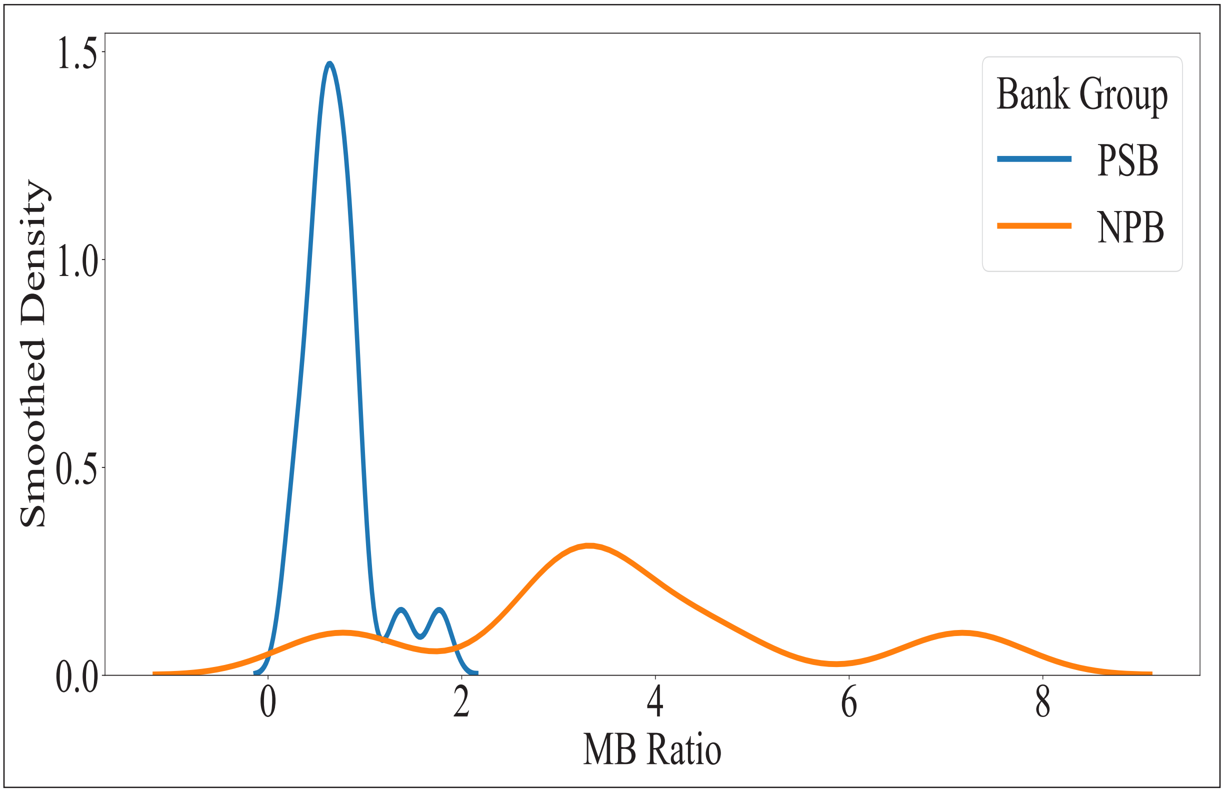

स्रोत: मनी कंट्रोल से प्राप्त आंकड़े

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मध्य और नए निजी बैंकों के मध्य विविधता तुलना

7.24 इस बात का सावधानी पूर्वक उल्लेख किया जाना चाहिए कि क्यों सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के औसत निष्पादन और नए निजी बैंकों में औसत निष्पादन के बीच तुलना एक उपयुक्त, 'सेब से सेब' तुलना होती है। किसी भी आर्थिक क्रियाकलाप के साथ, निष्पादन में विविधता का होना अवश्यम्भावी होता है। क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच भी उनके निष्पादन में बड़ा अंतर होता है, सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों का निष्पादन अन्य बैंकों की तुलना मे बेहतर होता है; इसी प्रकार, नए प्राइवेट बैंकों के निष्पादन में भी ऐसा ही अंतर होता है। किंतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के औसत निष्पादन की साथ तुलना और किसी नए प्राइवेट बैंक के कमजोर निष्पादन के साथ तुलना सही नहीं है क्योंकि इसमें दो सांख्यिकी उपाय-औसत एवं इनके विचलन को शामिल किया जाता है तथा ''एप्पल-से-औरेंज'' तुलना की ओर अग्रसर होता है। इसी प्रकार, नए प्राइवेट बैंकों के निष्पादक में भी ऐसा ही अंतर होता है। किंतु, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के औसत निष्पादन की नए प्राइवेट बैंक के बेहतर निष्पादन के साथ तुलना और किसी नए प्राइवेट बैंक के निकृष्ट निष्पादन के साथ तुलना सही नहीं है क्योंकि इसमें दो सांख्यिकीय मापकों - औसत एवं इनके विचलन को मिश्रितकर लिया जाता है तथा यह ''सेब से संतरे की'' तुलना की और ले जाता है।

7.25 निष्पादन में विविधता के लेखाकरण द्वारा तुलना करने के लिए हम चित्र 16 के बाक्स प्लाटों में पीएसबी तथा एनपीबी के लिए आरओए के वितरण का निरीक्षण करते हैं। बाक्स प्लाट को समझने के लिए बॉक्स 3 देखें) इस चित्र से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2013 से प्रत्येक वर्ष के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले पीएसबी का आरओए खराब प्रदर्शन करने वाले एनपीबी के आरओए से कम है। इसी प्रकार का दृश्य, यद्यपि कुछ कम, आरओई में भी दिखाई दिया है।

चित्र 16क: परिसपत्तियों पर प्रतिप्राप्ति में विविधता

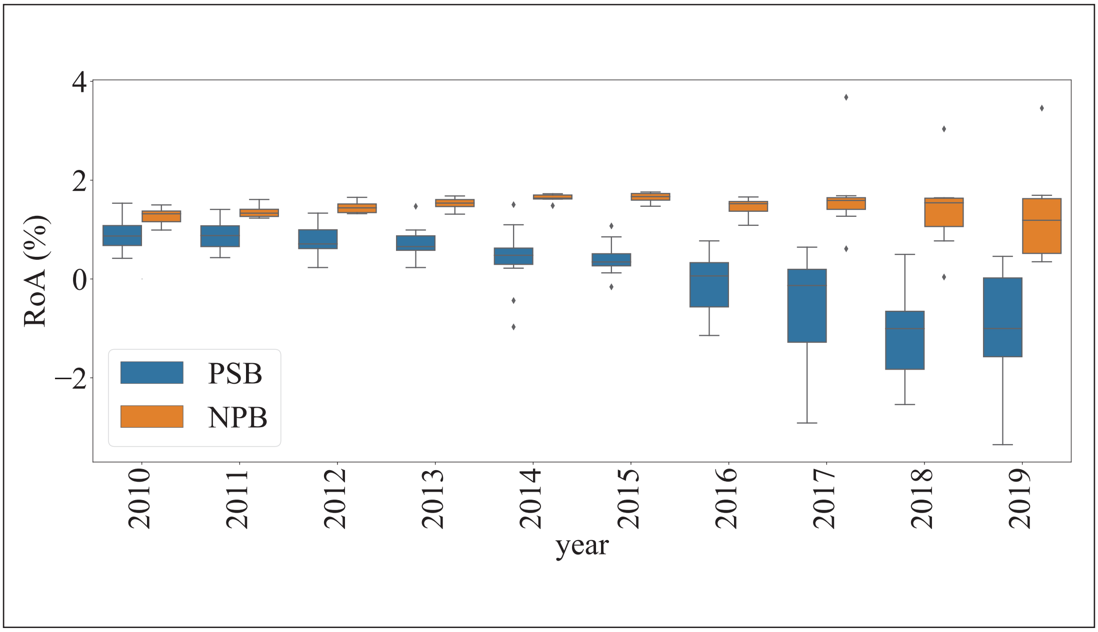

स्रोत: आरबीआई आकड़े और समीक्षा परिकलन

चित्र 16ख: इक्विटी पर प्रतिप्राप्ति में विविधता

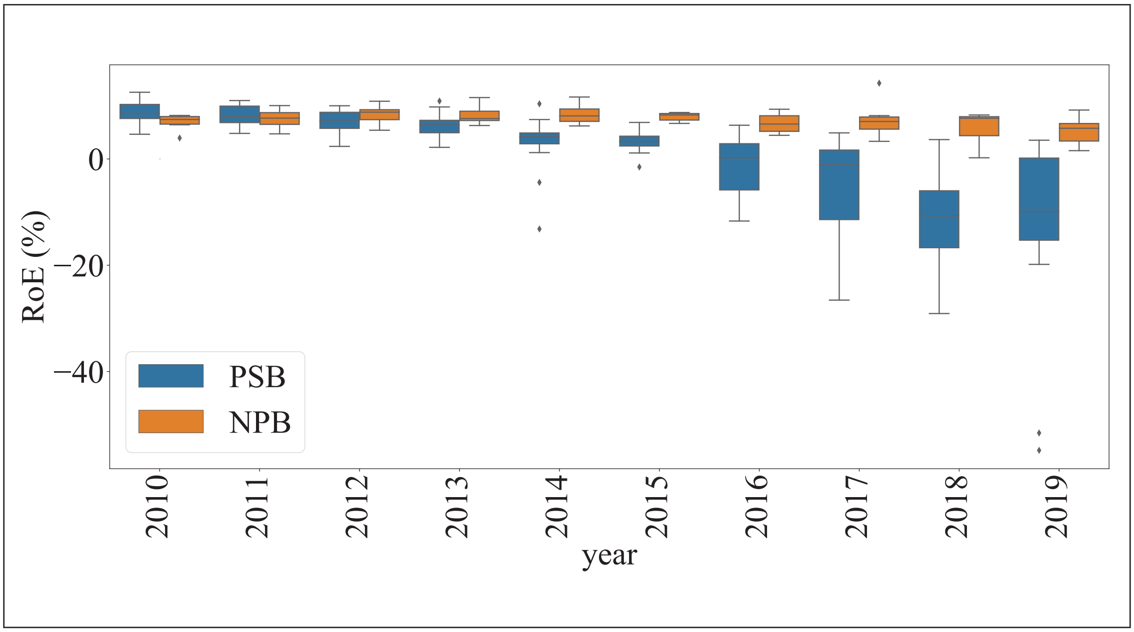

स्रोत: आरबीआई आकड़े और समीक्षा परिकलन

बॉक्स 3: बॉक्स प्लाट की व्यवस्था

बाक्स प्लाट में (क) न्यूनतम को क्षेतिजाकार रेखा से निरूपित किया गया है, (ख) आयत के निचली रेखा द्वारा निरूपित प्रथम चतुर्धाशं (ग) आयात के अंदर की रेखा द्वारा निरूपित माध्यिका, (घ) आयत की शीर्ष रेखा पर द्वारा निरूपित तीसरा चतुर्थांक (ड.) सबसे ऊपरी क्षेतिजाकार रेखा द्वारा अधिकतम को निरूपित किया जाता है।

7.26 ये सांख्यिक विरोष रूप में प्रभावकारी हैं चूंकि दोनों, एनपीवी एवं पीएससी, एक ही घरेलू बाजार में प्रचालित होते हैं। फिर भी, हमें बैंक निष्पादन में अनियमितता दिखाई देती है जिससे पिछले दशक में इन्हें विशेषरूप में विभाजित किया है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि स्थितियां निश्चित रूप से पिछले दशक मे बैंकों द्वारा लिए गए खराब निर्णयों को निरूपित नहीं करती। विश्व में वित्तीय संकट का इतिहास यह दर्शाता है कि खराब अधिशासन का प्रभाव केवल खराब समय में दिखाई देता है, कभी-भी अच्छे समय में नहीं। जैसा कि 2014 पी.जे. नायक समिति रिपोर्ट में दर्शाई गई पीएसबी की संचालक कमजोरी उनके खराब निष्पादन को ही व्यक्त करती है।

7.27 कुछ लोग तर्क देते हैं कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस कमजोर कार्य निष्पादन का दौर अब जा रहा है। हालांकि, इस व्याख्या में आवश्यक रूप से बैंकिंग क्षेत्र के संकट के पूर्व काल के बारे में सारभूत ज्ञान की कुछ उपेक्षा प्रतीत होती है, जिससे हमें यह पता चलता है कि बैंकिंग क्षेत्र का खराब कार्य निष्पादन अपरिहार्य रूप से अनेक प्रणालीगत कारकों से उत्पन्न हुआ है। जैसा कि लेवेन (2011) रेखांकित करते हैं कि बैंकिंग संकट के कारणों में अवहनीय समष्टि अर्थशास्त्रीय नीतियों, बाजारीय विफलताओं, विनियामक विकृतियों एवं पूंजी आवंटन में सरकारी हस्तक्षेप का एक संयुक्त रूप शामिल है। इसके अलावा जिन संकटों का प्रभावी तरीके से और तत्परता से समाधान न किया जाए वे समाज को व्यापक हानि पहुंचाने का कार्य करते है।

पीएसबी की दक्षता बढ़ाना: भावी परिदृश्य

7.28 अब भारत की संवृद्धि संभाव्यता के महत्वपूर्ण चालक (क) अनुकूल जनसांख्यिकी 15 से 29 वर्ष के बीच की 35 प्रतिशत आबादी; (ख) आधुनिक एवं आधुनिक डिजीटल अवसंरचना जिसमें 'जेएएम' त्रिमूर्ति वित्तीय समावेशन आधार विशिष्ट पहचान प्रणली एवं सुविकसित मोबाइल फोन नेटवर्क को शामिल किया गया है एवं (ग) अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली हैं ताकि विखण्डित, जटिल राज्य स्तरीय प्रणाली को प्रतिस्थापित किया जा सके।3 भारत की प्रगति का मार्ग इस पर निर्भर करता है कि सुविकसित वित्तीय प्रणाली का प्रयोग कर इन विकास लीवरों का कितना त्वरित एवं उत्पादकता पूर्ण ढंग से नियोजन किया जाता है।

7.29 पहले पीएसबी की दक्षता में वृद्धि करने के लिए नरसिंहा समिति (1991, 1997) राजन समिति (2007) एवं पीजे नायक समिति के अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं। अत: समीक्षा में पीएसबी दक्षता को बढ़ाने के लिए दो विचारों पर बल दिया गया है जिन पर अभी कार्य नहीं किया गया है।

कृत्रिम आसूचना एवं मशीन शिक्षण का प्रयोग करके साख विश्लेषण

7.30 आज भारत के विकास अवसर जो कि अनेक सकारात्मक स्थितियों के अनोखे संगम से उपजता है जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक फिन टेक का सही अर्थो में उपयोग करने की स्थिति में आते हैं। इनमें से एक भारत का जनसांख्यिकी अंश है। भारत की 62 प्रतिशत आबादी 15 और 60 के बीच में है। इसके अतिरिक्त आबादी का 30 प्रतिशत 15 से नीचे की है। अत: भारत लंबे समय तक महत्वपूर्ण कार्यशील आयु वर्ग के लाभों को लेने के लिए तैयार है। भारत के विकास अवसरों को गति देने के लिए जो दूसरा कार्यबल है वो जेएएम ''ट्रिनीटी'' है उदाहरणार्थ प्रधानमंत्री जन धन योजना बैंक खाता कार्यक्रम, विशिष्ट पहचान पत्र कार्यक्रम और मोबाइल फोन अवसंरचना जिनमें से प्रत्येक को व्यवहारिक तौर पर पूरे देश को शामिल करने के लिए क्रियान्वित किया गया। इन दो कारकों के परिणामस्वरूप डिजिटल लेन-देनों में वृद्धि उल्लेखनीय रही। (चित्र 17)। सापेक्ष लाभ अंतरणों जोकि गत पांच वर्षों में तेजी से बढ़ा है (चित्र 18), से बैंकिंग प्रणाली में सात और जमा दोनों ही सम्पूर्ण भू-भाग में लाने में सहायता मिली (चित्र 19)। ग्रामीण, अर्धशहरी, और महानगर (चित्र 19) में सभी भू-भाग पर दर्शायी गई उच्च लोच सरकार द्वारा डीबीटी के अधिकतम उपयोग से लाभ प्राप्त करने हेतु भारतीय बैंकों के लिए मौजूदा अवसरों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

[4] जेएएम ट्रिनीटी डिजीटल अवसंरचना का समर्थन करती है। ''प्रधानमंत्री जन धन योजना'' बैंक खाता में 37.8 करोड़ लाभार्थियों ने नामांकन किया जिनके बैंक बैलेंस 1.11 लाख करोड़ के पार हो गया। 120 करोड़ से अधिक विशेष पहचान पत्रों को जारी किया गया। 137 करोड़ की भारत की जनसंख्या के लिए 128 करोड़ मोबाइल फोनों और यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस को दिए गए।

7.31 उपर्युक्त सभी संभावनाऐं यह दर्शाती हैं कि भारतीय बैंक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के स्तर के अनुपात में विकास करे। नए कार्यक्रम औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाये जा रहे व्यक्तियों एवं व्यापार के

चित्र 17: मार्च 2016 – जनवरी 2019 के बीच डिजिटल लेनदेन का कुल मूल्य

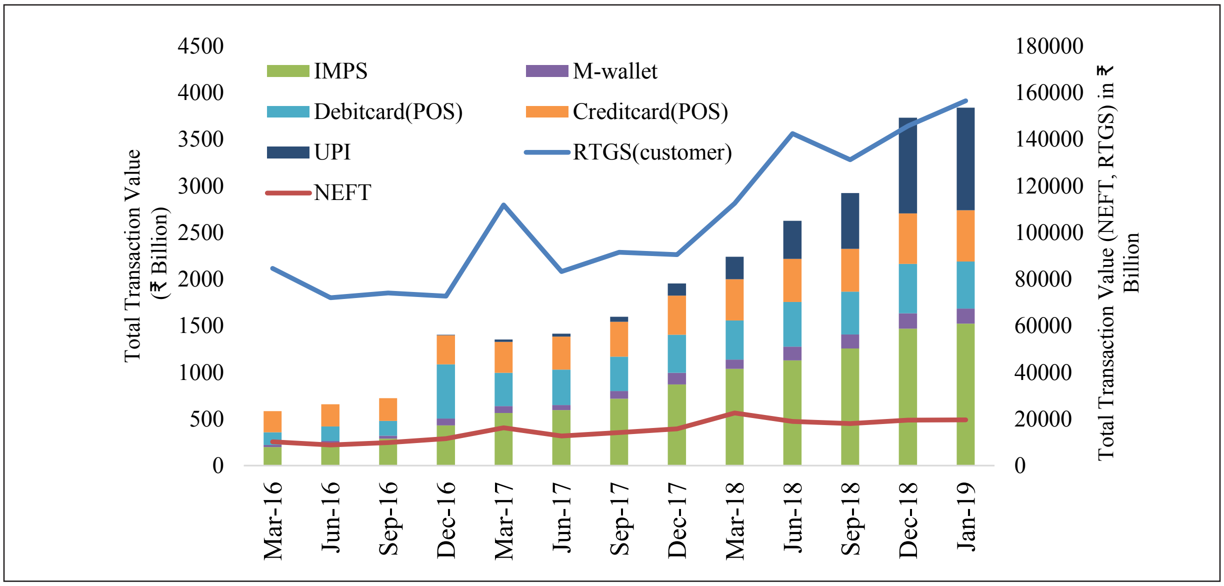

स्रोतः भुगतान प्रणाली सूचकांक, आरबीआई

चित्र 18: अंतरित राशियों के रूझान तथा डीबीटी स्कीमें

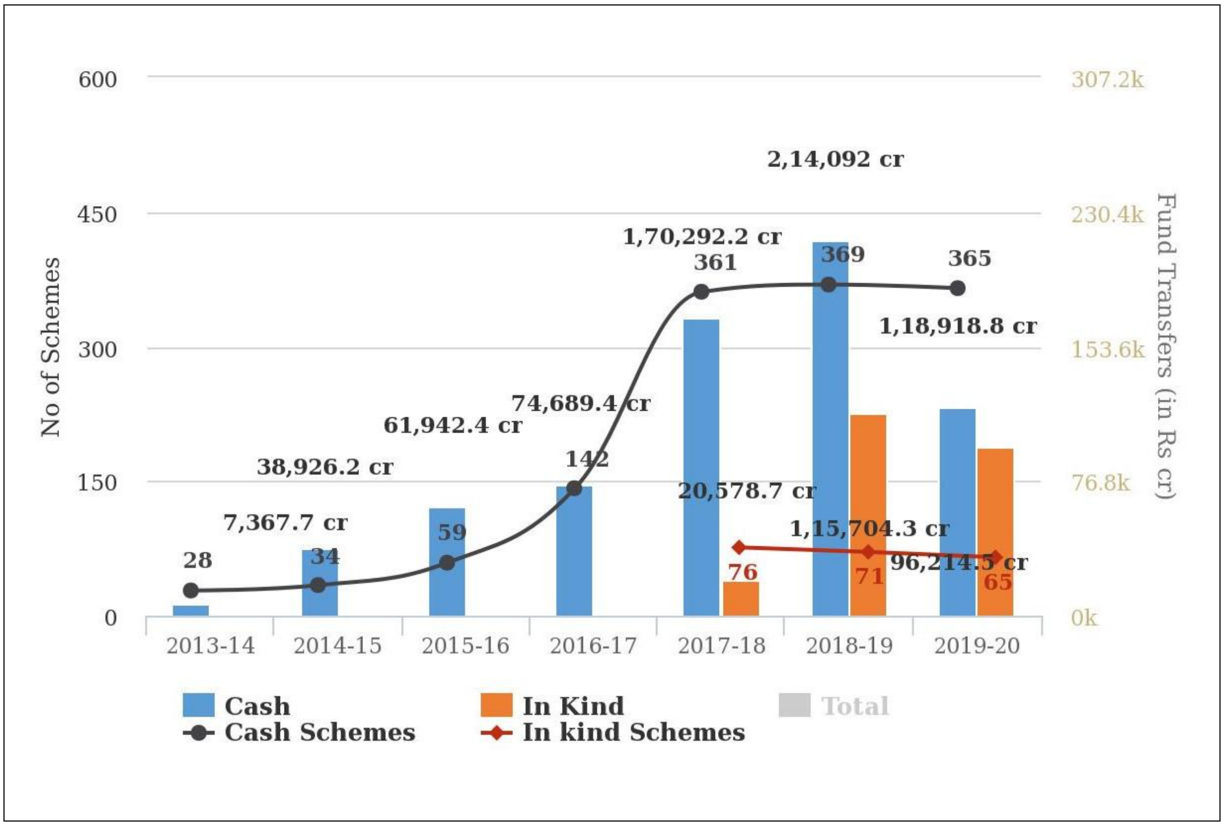

स्रोतः डीबीसी

चित्र 19: बैंकिंग सिस्टम के लिए डीबीटी के लाभ

(क): ऋण **(ख): जमा**

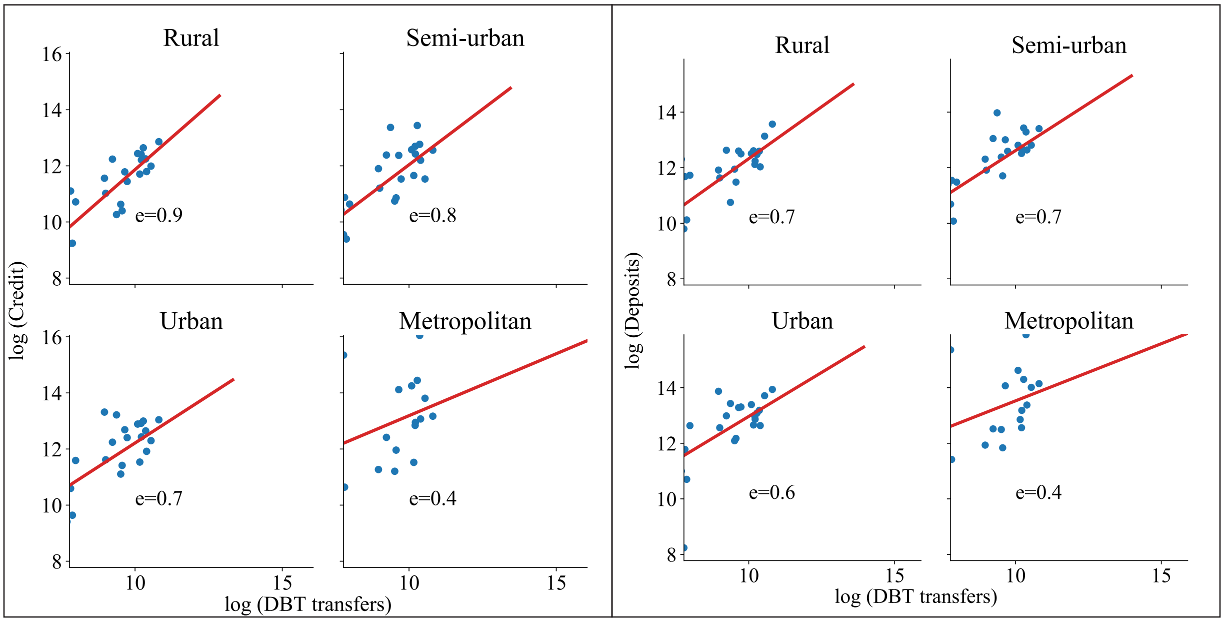

स्रोत: डीबीटी, आरबीआई और समीक्षा परिकलन

आवेश परिणामस्वरूप है। यद्यपि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि अत्याधुनिक डिजिटल अवसंरचना जो कि सभी फर्मों के आर्थिक गतिविधियों पर बहुतायत में उच्च गुणवत्ता संरचनात्मक आंकड़ों को सृजित और एकत्रित करता है। ऐसे आंकड़े आवश्यक ही 21वीं सदी की आर्थिक वृद्धि के लिए सोने की खान है। विशेषरूप से फर्मों और व्यक्तियों जो परंपरागत रूप से वित्तीय प्रक्रिया से अलग किए गए हैं उनके लिए अनिवार्य असीमित और गैर सूचित संभावनाएं प्रदान करते हैं।

7.32 पीएसबी के पा अनेक महत्वपूर्ण पदार्थ है जिनसे नई मांगों को पूर्ण किया जा सकता है? उदाहरण के लिए, उनके पास स्थानीय बाजार नजर और अनेक दशकों की ऐतिहासिक परिचालन पर आधारित है। उनकी भौगोलिक पदचिन्ह बहुत बड़े हैं। यद्यपि, पीएसबी को भारत में आने वाले महत्वपूर्ण विनिवेशों की योग्यता की आवश्यकता है। बाजार पर आधारित विश्लेषण आंकड़े कार्पेरेट तलाव को सही अनुमानित करने में सक्षम है। इस प्रकार की पहुंच उपभोगता ऋण और व्यवसायिक एवंम औद्योगिक ऋण को पकड़ने का कदम रखते है।

7.33 वह आंकड़े जो कि ऋण विश्लेषण के लिए आवश्यक है वह संरक्षित और असंरक्षित रूप दोनों में ही उपलब्ध है। संरक्षित रूप में उपलब्ध आंकड़े ऋण सूचना और ऋण स्कोर ऋण के अनुमोदन पर आधारित है और पुर्नभुगतान ऋण रजिस्ट्री या ऋण ब्यूरो में होता है। पर्याप्त, हालांकि असंरिक्षत, सूक्ष्म आंकड़े विषय, भू-चिन्हित आंकड़े, सोशल नेटवर्क आंकड़े, मोबाइल एप, साथ ही साथ वर्तमान और भावी ग्राहकों के अन्य छोटे या गहरे डिजिटल फूटप्रिन्ट है। इन आंकड़ों का लाभ उठाने के लिए नये आंकड़ों, विश्लेषण और मॉडलिंग तरीके की आवश्यकता है। इसी तरह, बैंक को ऋण की वसूली अवसंरचना में निवेश करने की आवश्यकता है। इन नई तकनीकों के प्रयोग से आंकड़े से भरा हुआ माहौल को अतिरिक्त विनिवेश जैसे कि विशिष्ट मानव पूंजी की तरफ झुकाव है। ऐसी तकनीकों से रूकावट अजेय नहीं होती है। हालांकि ऐसे कुछ उदाहरण है जहां पीएसबी में कुछ ढ़ीलापन, तकनीकी

विरोध पीएसबी को कोई अन्तर्भूत विशेषता नहीं लगती है। उदाहरण के लिए, जब ऋण ब्यूरो को भारत में लाया गया था तब पीएसबी पूर्णत बहुत तेजी से नए ग्राहकों को लपकने में उत्तेजित था। (मिश्रा, राजन और प्रभाला, 2019)

ऋण विश्लेषण के लाभ

7.34 भारतीय बैंकों के एनपीए के बहुत बड़े भाग को बचाया जा सकता था यदि आंकड़े और विश्लेषण को कॉरपोरेट ऋण में नियोजित किया जाता। चित्र 10 यह दर्शाता है कि दोषपूर्ण ऋण की दर बहुत बड़े ऋणों (100 करोड़ से बड़े उच्चतर है। चित्र 21-24 विभिन्न मुख्य संकेतकों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है जो आंकड़े और विश्लेषण का प्रयोग कर जानबूझ वाले दोषियों को दिखा सकता था। चित्र 21 यह दर्शाता है कि संबंधित पार्टी अंतरण के खुलासे में चरणबद्ध अंतर, प्रोत्साहकों का शेयर की शपथ संबंधित पार्टियों के जानबूझकर दोषी और हताश दोषी के बीच है यह बड़े सरल मात्रानिर्धारक उपाय है जो कि एक मजबूत साख विश्लेषणात्मक संकेत प्रणाली देती है।

7.35 भारतीय रिजर्व बैंक ने जून, 2017 में 12 कंपनियों की पहचान की, जिनके पास भारत के कुल गैर निष्पादित संपत्ति का 25 प्रतिशत जमा था। ये 'डर्टी डजन' जैसे रेखा चित्र 22 में दिखाया है, 2012, 2013 और 2014 में अन्य समान सूचीबद्ध कॉरपरेट्स के माध्य लेखा गुणवत्ता से इनकी लेखा गुणवत्ता बहुत कम है। चूंकि लेखा गुणवत्ता आसानी से मापी जा सकती है, एक ठोस ऋण वैश्लेषिकी प्लैटफॉर्म आसानी से इसकी पहचान करके चेतावनी दे सकते हैं।

चित्र 20: गैर-निष्पादन परिसंपति (एनपीए) ऋण के आकार का रेट

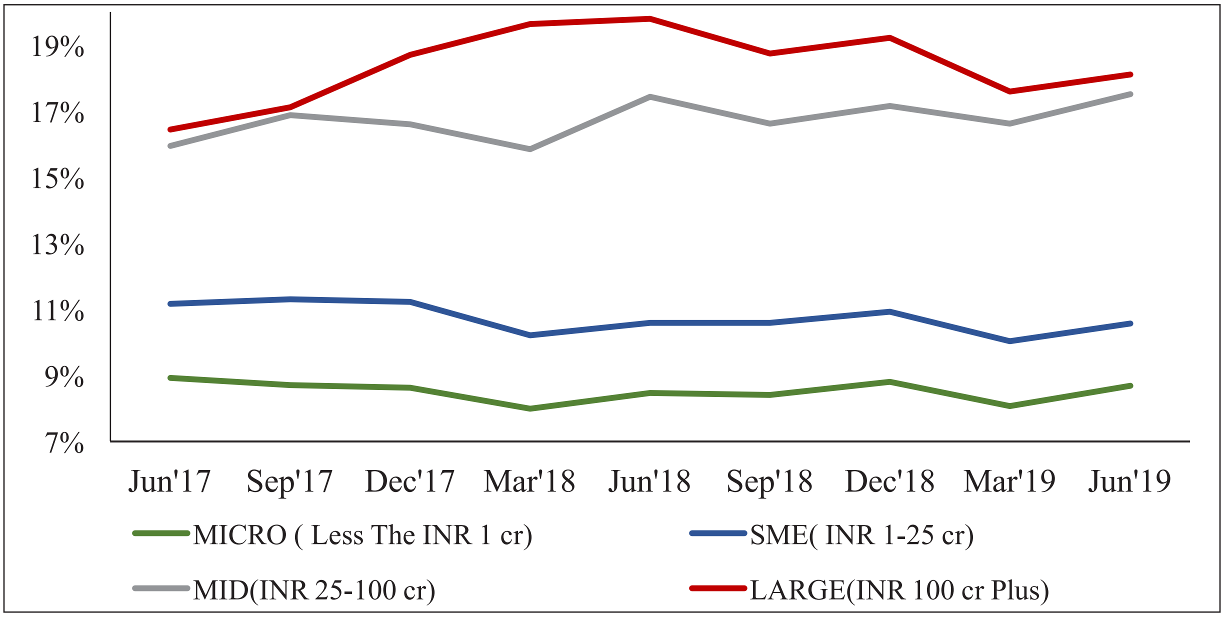

स्रोतः ट्रांस यूनियन सिविल सिडबी

7.36 इन बड़े दोषियों की वार्षिक रिपोर्ट का विश्लेषण यह सूचित करता है कि इन कंपनियों की लेखा परीक्षा प्रकटीकरण बहुत कमजोर है। जैसे रेखांचित्र 23 में देखा

चित्र 21: संबद्ध पक्ष लेनदेन, संस्थापकों के शेयर गिरवी रखे जाने ताा संबद्ध पक्षों को बड़े ऋण आदि के प्रमुख संकेतक।

पैनल 'क' जनाबूझकर तथा विवश दोषियों की तुलना | **पैनल बी: जानबूझकर दोषियों और गैर-विवरण दोषियों की तुलना**

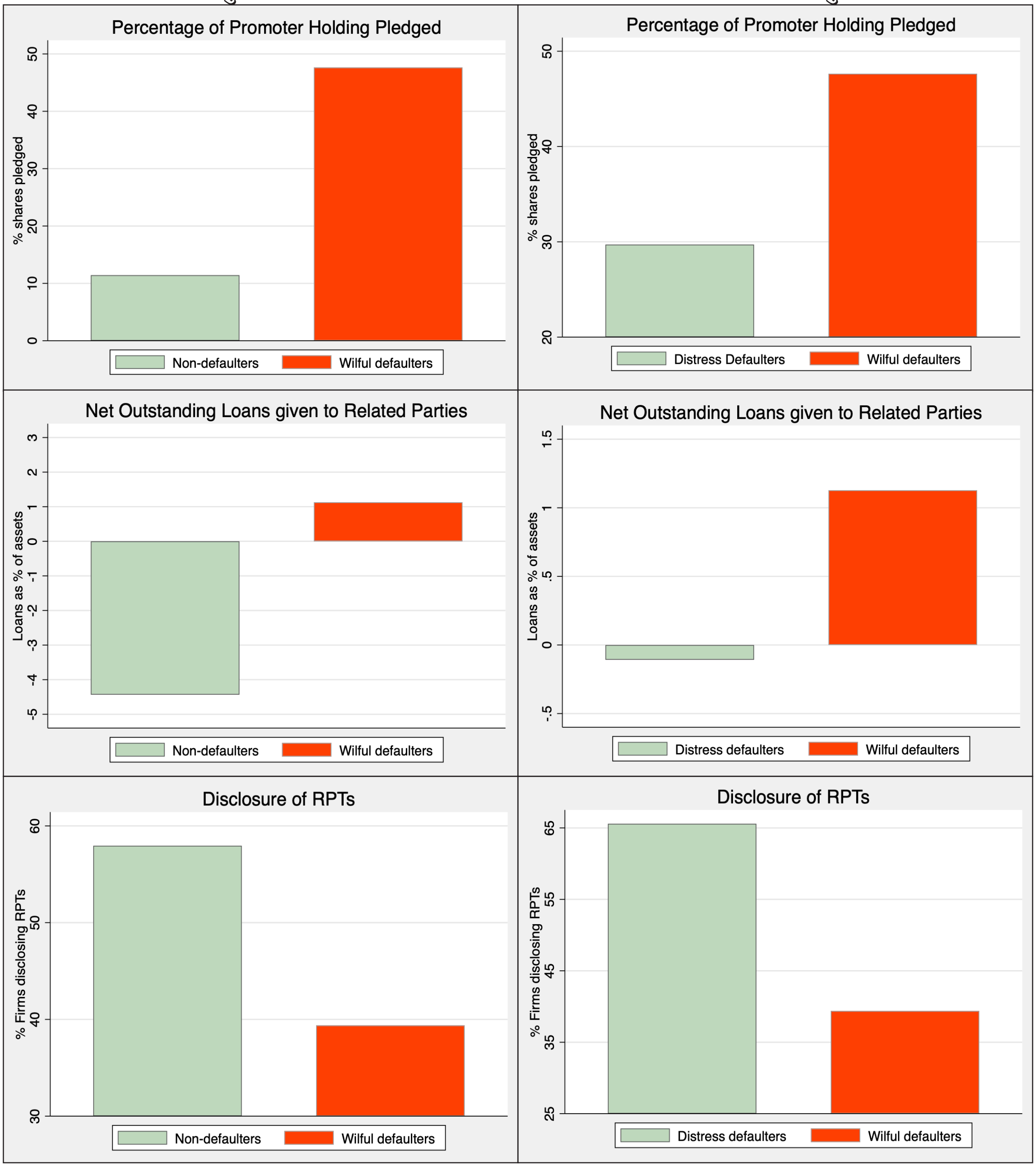

स्रोत: सीएमआईई कौशल, ट्रांसयूनियन सीबीएल सूटस फाईड डाटाबेस,

टिप्पणी: एक फर्म को एक आरपीटी खुलासा बनाना है यदि इसके वार्षिक फाईलिंग में आरजीपी सेक्शन निहित हैं (भले ही कोई फर्म यह कहती है कि उसने वर्ष में कोई भी अंतरण नहीं किया है) कुल बकाया ऋण, फर्म द्वारा उनकी संबंधित पार्टी को दिए गए ऋण के कुल शेष को दर्शाता है। जानबूझकर दोषी वह कहलाते है जो कि सीबीएल सूटस फाईड डाटाबेस में वर्गीकृत किए गए है। जबकि हताश दोषी वह हैं जो किसी सैंपल अवधि में दोषपूर्ण क्रेडिट रेटिंग में केवल एक वार दोषी पाए गए लेकिन वह जानबूझकर दोषी की श्रेणी में नहीं है। गैर दोषी अन्य फर्में हैं। यह आंकड़े 2002-18 तक विस्तारित हैं।

चित्र 22: बड़े दोषियों के लिए लेखा गुणवत्ता उपायों से स्पष्ट प्रमुख सूचक

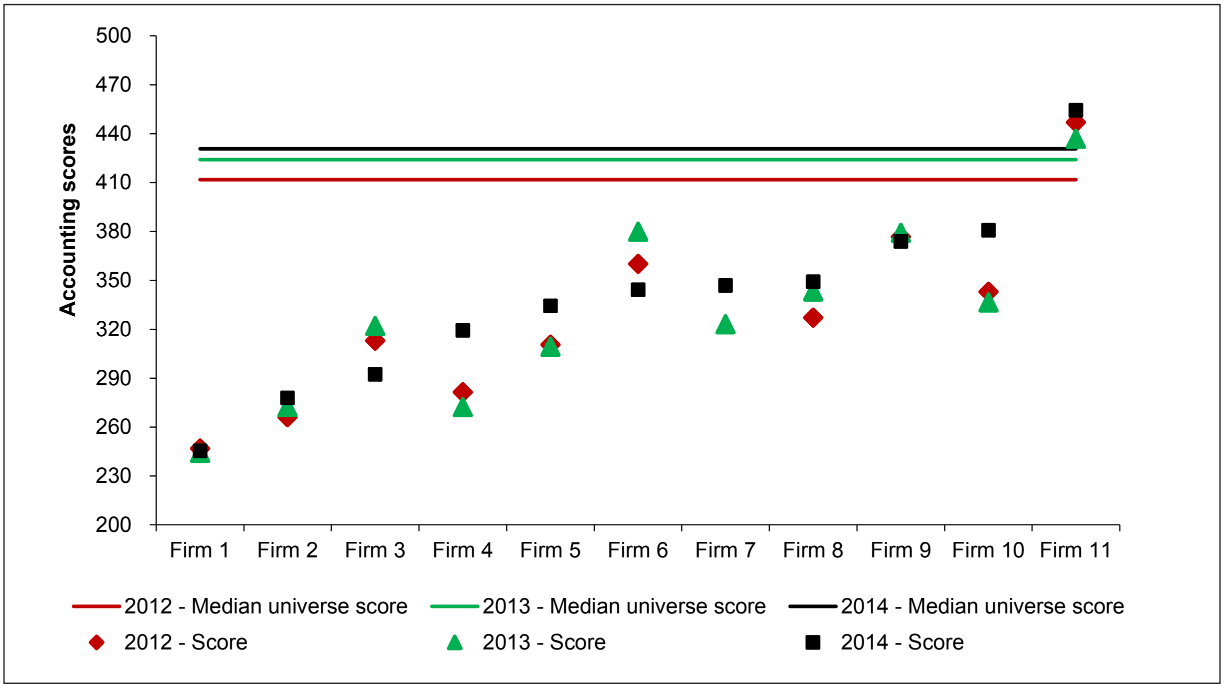

स्रोत: कंपनी वित्तीय, दिवाला और दिवालियापन बोर्ड ऑफ इंडिया

जा सकता है, इनमें से एक का सिर्फ एक संकेतक का प्रकाशन हुआ है जबकि तीन से चार संकेतकों वाले अन्य लोगों ने अग्रणी और विलंबित संकेतकों का खुलासा किया है। पुन: यह एक आसानी से नापने योग्य लक्षण है, जिसकी पहचान एक ठोस ऋण वैश्लेषिकी प्लैटफार्म आसानी से कर सकता है।

7.37 रेखाचित्र 24 दर्शाता है कि 2014 तक उधारदाताओं के बीच एनपीए पर जानकारी साझाकरण

चित्र 23: बड़े दोषियों के वित्तीय विवरण से उदघाटित अग्रणी और पिछड़ा संकेतक

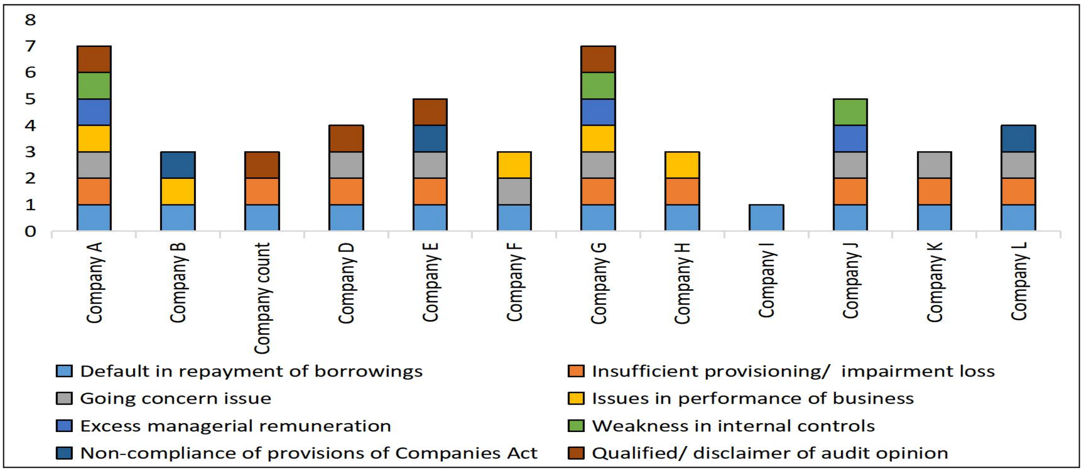

स्रोत: कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट तथा समीक्षा परिकलन

न्यूनतम था। जबकि पीएसबी में जानकारी साझाकरण एनपीवी से ज्यादा बेहतर था, अन्य बैंकों द्वारा एनपीए घोषित बैंक खातों में से लगभग एक चौथाई, एनपीए के रूप में वर्गीकृत थे। कुछ ही सालों में इस अनुपात में नाटकीय वृद्धि हुई है और यह 95 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

चित्र 24: अन्य बैंकों द्वारा अपनी बहियों में एनपीए घोषित ऋणदाताओं का पहले से ही घोषित किए जा चुके एनपीए से अनुपात

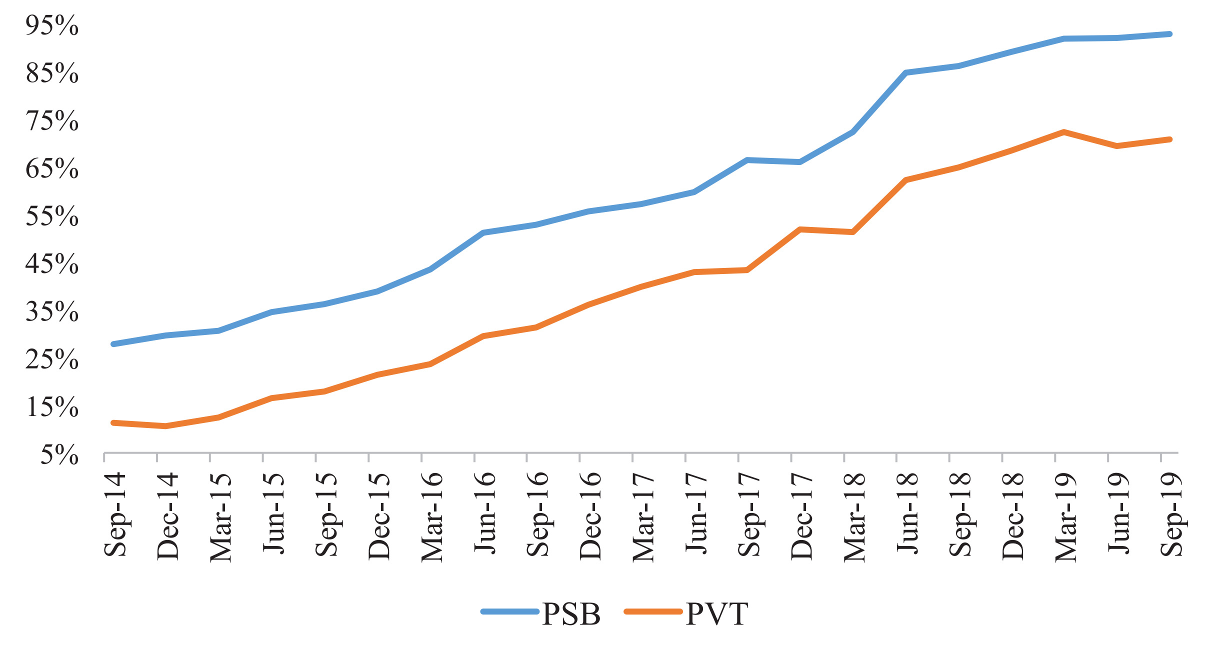

बॉक्स 4: लेनदारों की कोलिटरल बचाने के लिए लेवरेजिंग आंकड़ों पर एक नोट

बॉक्स 4: अधिकतर कारपोरेट अवधि ऋण सुरक्षित होते हैं और ऋणदाताओं के पास अपनी संपत्ति को ऋण की गैर अदायगी की स्थिति में शपथ पर रखते हैं। हालांकि, जब जानबूझ कर की गई गैर अदायगी से सरोकार रखा जाता है तो ऋणदाता अपने हाथों को बंधा हुआ महसूस करता है चाहे वह शपथ परिसंपत्तियों ही क्यों न हों। जब जानबूझ कर की गई चूक वाले लोगों के पास एक आसान तरीका होता है अपनी कोलट्रल की कीमत को गलत बताने का। अधिक खराब मामलों में, यह लोग झूठी कोलट्रल की शपथ लेते हैं। यदि ये वास्तिविक कोलट्रल की शपथ लें तो उनके पास उन संपत्तियों को बिना ऋणदाता के जानकारी के निपटा देने का नियंत्रण होता है या अपनी संपत्तियों से नियंत्रण को चूक की स्थिति में खो देते हैं।

इन मामलों में आंकड़े ऋणदाताओं के पास आते हैं। उदाहरण के लिए जीओ टैगिंग – छवियों, वीडियो या अन्य मीडिया में चौड़ाई और लंबाई जैसी भौगोलिक पहचान को लगाने की प्रक्रिया – जो कि ऋणदाताओं को परिसंपत्तियों की लोकेशन को पकड़े रखने में सहायता देती है। यदि ऋणियों को सम-समायिक रूप से अपने कोलट्रल संपत्तियों की जीओ टैग प्रमाण अपने ऋणदाताओं से साझा करनी पड़े तो उनके लिए इन परिसंपत्तियों को चोरी से हटाना मुश्किल होगा। विभिन्न सरकारी विभागों ने पहले से ही जीओ टैगिंग में बढ़त ले ली है; ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा संपत्तियों को जीओ टैग करता है और भूमि संसाधन विभाग में वाटरशेड परियोजनाओं में जीओ टैग किया है। इन उदाहरणों से ऋणदाता अपनी कोलट्रल की निगरानी करना सीख सकते हैं। जीओ टैग शपथ की गई भूमि या संपत्ति की कीमत को जांच सकती है। भूमि की सही लोकेशन को पकड़ सकती है, ऋणदाता इन संपत्तियों की बाजारी कीमत को बढ़िया तरीके से मूल्यांकित कर सकती है, और ये सब सूचनाएं लोकेशन से प्राप्त हो सकती हैं।

जीपीएस प्रणाली से और अधिक निगरानी की जा सकती है। जीपीएस उपकरणों को जब मशीनों या उपकरणों से जोड़ा जाता है तब यह ऋणदाताओं को संपत्तियों को हटने की स्थिति में सावधान करती है। यह नजर रखने वाली प्रणालियों यह सुनिश्चित करती हैं कि संपत्तियां ऋणदाताओं की नजरों से गायब न हों। उदाहरण के लिए किराये पर देने वाली

कंपनियां लैपटॉप, उपकरणों इत्यादि को लीज़ पर देती हैं, ने इस जीपीएस निगरानी का इस्तेमाल बहुत अच्छे ढंग से किया है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण अधिकांश एक ऐसे रिमोट स्विच के साथ आते हैं जिसको यदि किरायेदार खराब करने की कोशिश करे, निपटान करने की कोशिश करे या किराया देने में देरी करे तो उसकी सभी कार्यप्रणाली को बंद किया जा सकता है। वास्तव में यह ऋणदाताओं के लिए बहुत ही अच्छा उपकरण है क्योंकि यदि ऋणदाता ऋण का जानबूझ कर भुगतान न करे तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। किंगफिशर एअरलाईन ने ऋण प्राप्ति के लिए कुछ हैलीकॉप्टरों की (अन्य संपत्तियों के साथ) शपथ लिया था। जब ऋणदाता इन संपत्तियों का अधिकार लेना चाहता है तो क्या वह यह महसूस करता है कि हैलीकॉपटर की स्थिति खराब हो चुकी है और यह केवल कबाड़ी कीमत से कुछ ज्यादा ही निकाल पायेगी। इन सब में कम खर्च वाली तकनीक को संपत्ति की उपस्थिति के इस्तेमाल और गुणवत्ता को जानने के लिए किया जाता है।

किसी क्षेत्र में सभी ऋणदाताओं की संपार्श्विकता परसमेकित डाटा विशेषरूप से उसके दोबार गिरवी रखने की संभावना को कम करने में सहायक है उदाहरण के लिए के पक्षकार एक ही संपर्श्विक संपत्ति को एक ही परियोजना के लिए कई बार उधार लेने के लिए कई ऋणदाताओं या खरीददार या दोनों को अलग-अलग एक ही व्यापार के लिएउनके संबंधित ऋणदाताओं को एक ही बीजक पर उसनी संपार्श्चिक संपत्ति गिरवी रख सकता है। जब तक ऋणदाता, व्यापारियों का सत्यापन करने के लिएमानवीय नियंत्रण प्रक्रियाओं या दस्तावेज आधारित प्रलेखन पर निर्चर रहेंगे तब तक इस प्रकार की दोहरा गिवी रखना जारी रहेगा। स्विफ्ट इंडिया जिस मैसंजिंग प्लेटफार्म का पंजाब नेश्नल बैंक ने नीवर मोदी मामले मे संदेश संप्रेषित करने के लिए किया था उसमें एक ऐसी प्रायोगिक ब्लॉक चेन प्रयास की घोषणा की गई है जो ऋणदाताओं को उन्हें ऑनलाइन प्रस्तुत किए गए ई-बिल तथा बीजक लॉक करने की अनुमति प्रदान करता हैं तथा अल्प ऋणदाताअें को यह सत्यवित करने में सक्षम बनाता है कि वे जिस व्यवसाय के लिए वित्त पोषण करना चाहते हैं क्या वह पहले से ही वित्त पोषित तो नहीं है या उसमें निहित संपार्श्विक संपत्ति पहले से ही बंधक तो नहीं पड़ी है। इस प्रकार की एकीकृत डाटा प्रणाली ऋणदाताओं के संरक्षण प्रदान करने के लिए निवार्य है।

जहां ये प्रौद्योगिकी सशक्त हैं वहीं दूसरी ओर इनके साथ एक महत्वपूर्ण जोखिम भी जुड़ा रहता है अर्थात उधारकर्ताओं की प्राइवेसी और सम्मान के अंतर्गत का जोखिम। ऋणों के दायित्वों को लागू करने में उधारकर्ता के निजी क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए जब तक कि उधारकर्ता को उसके जानबूझ कर चूक करने का संदेह न हो। इसलिए जो भी डाटा एकत्रित किए जाएं, कैसे, किसके द्वारा और कब तक के, अनेक संबंध में प्रबल और स्पष्ट दिशानिर्देशों की आवश्यकता होती है।

सारांश रूप में जानबूझ कर चूक का अर्थव्यवस्था की मजबूती पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि उधारदाता गिरवी रखी गई परिसंपत्तियों को बेच कर अपनी देय राशि को पूरी तरह वसूल कर ले। प्रौद्योगिकी और डाटा का इन परिसंपत्तियों को सुरक्षित और बिक्री योगय बनाए रखने के लिए प्रबलता से उपयोग किया जा सकता है। वास्तव में मूल्यवान परिसंपत्तियों को लोन का खतरा प्रथम दृष्या जानबूझ कर चूक रोकेगा क्योंकि ये फर्म अक्सर तभी जानबूझ कर चूक करती हैं जब उन्हें अपनी मूल्यवान गिरवी रखी परिसंपत्तियों पर नियंत्रण खो देने का भय नहीं होता।

खुदरा ऋणों पर कॉरपोरेट उधार हेतु ऋण विश्लेषणात्मक उपायों का प्रयोग सीखना

7.38 भारत में खुदरा उधार देने के संबंध में वर्ष 2007-2008 के बाद काफी कष्टदायक और अनुभव से सीख भरा रहा है। खुदरा ऋणों में एनपीए ने प्राथमिक तौर पर एनपीबी द्वारा दिए असुरक्षित शामिल हैं। यद्यपि एनपीए का आकार एक प्रणालीगत परिप्रेक्ष्य से उल्लेखनीय था, इस क्षेत्र ने इससे काफी अनुभव प्राप्त किया है। जैसाकि चित्र 25 में देखा गया है, विभिन्न खुदरा उत्पादों में एनपीए स्तर वर्ष 2016-19 के दौरान 5 प्रतिशत से कम रहा। जहां विश्लेषकों के प्रयोग और बकायों में कमी आई है, उनसे महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त होते है जो कि भारत में कॉरपोरेट लेन-देन में कार्यान्वित की जा सकती है।

7.39 वास्तव डाटा और साख विश्लेषणों, जैसे कि ग्राहक साख ब्यूरो डाटा से खुदरा उधारी में उल्लेखनीय रूप से विकास को बढ़ावा मिला है। जैसा कि चित्र 26 में दर्शाया गया है, भारत में क्रेडिट ब्यूरो डाटा का उपयोग करते हुए शामिल की गई आबादी ो अनुपात में ओईसीडी अर्थव्यवस्थाओं के निकट पहुंच गया है। यहां 2006 से साख ब्यूरो के आंकड़ों में महत्वपूर्ण वृद्धि दर है (चित्र 27)

चित्र 25: मुख्य उत्पादों के आधार पर (2016-19) द्वारा खुदरा ऋणों में एनपीए स्तर

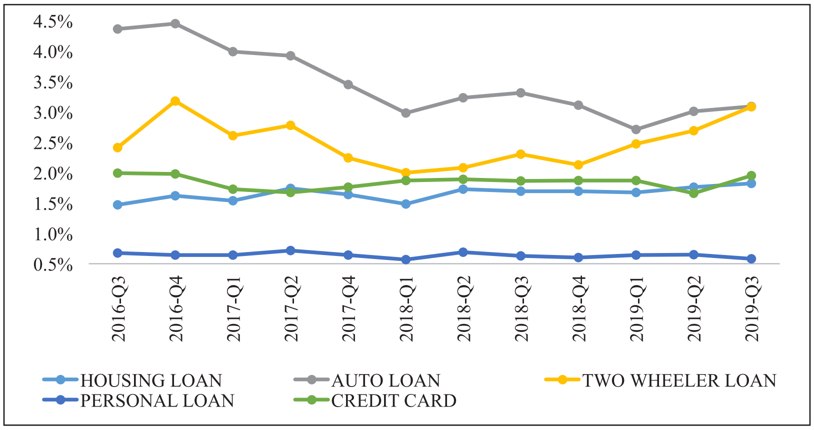

स्रोत: सिबिल डाटा

चित्र 26: भारत ओईसीडी क्रेडिट ब्यूरो कवरेज (प्रौढ़ आबादी का प्रतिशत) के साथ

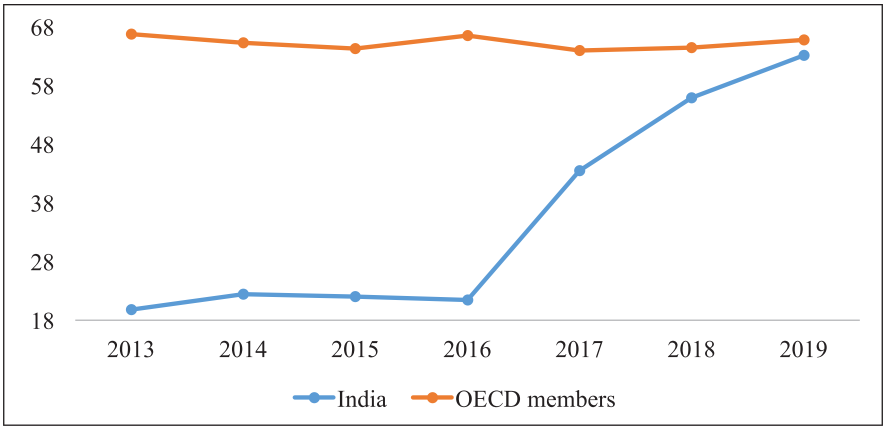

स्रोत: विश्व बैंक-ईज ऑफ डूइंग विजनैस रिपोर्ट 2019

चित्र 27: नए निजी क्षेत्र के बैंकों में क्रेडिट ब्यूरो डाटा के उपयोग में भारत ओइसीडी देशों के निकट पहुंचा

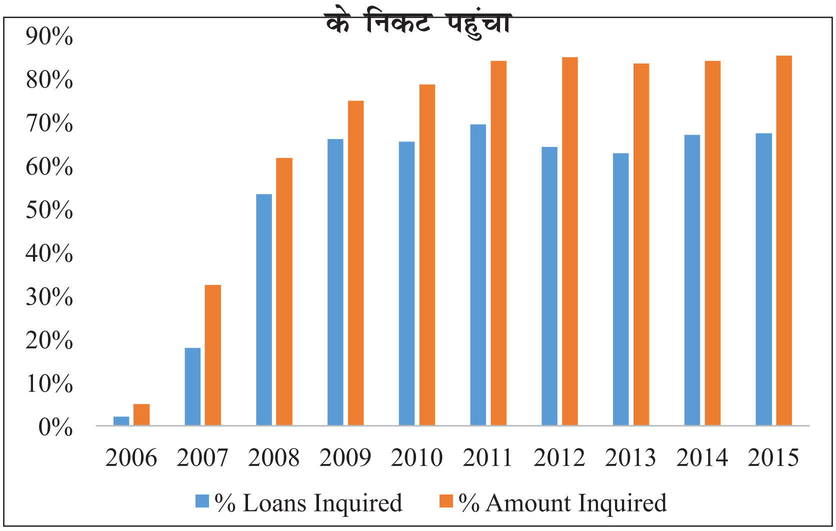

स्रोत: मिश्रा, प्रभाला, राजन, 2019

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों हेतु फिन टैक हब का निर्माण: सार्वजनिक क्षेत्र बैंकिंग नेटवर्क (पीएसबीए)

7.40 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ब्यूरो द्वारा (मिश्रा, राजन और प्रभला, 2019) क्रेडिट स्कोर अपनाने में तीव्र रहे। इसी प्रकार से उन्हें फिन टैक अपनाने की आवश्यकता होगी जो कि वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में क्रांति ला रहा है। फिन टैक पारंपरिक बैंकों को प्रभावशाली, निम्न-लागत, बैंकिंग समाधानों के साथ आकर उनके समय के साथ पुराने पड़ चुके व्यावसायिक आदर्शों की समीक्षा करने हेतु उन पर दबाव डाल रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को फिन टैक से अधिकाधिक लाभ लेना होगा क्योंकि उनका पारंपरिक सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग भी कुछ महत्वपूर्ण बैंकिंग समाधानों को छोड़कर उतन व्यापक नहीं है। अभी तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रौद्योगिकी का उपयोग मुख्यत: एमआईएस और रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है जबकि ऋण से संबंधित अधिकांश सूचना प्रसंस्करण व्यक्तिगत आधार पर ही किया जाता है जिससे प्रभावहीनता, धोखाधड़ियों और ऋण दोष उत्पन्न होते हैं। सूचना प्रक्रमण में संभावित लेनदारों की प्रत्याशित जांच और निगरानी पश्चात् उनके व्यवहार से संबंधित सभी गतिविधियां शामिल है।

7.41 फिनटेक ने बैंकों द्वारा संसाधित की जाने वाली सूचना को मौलिक रूप से बदल दिया है। उदाहरणार्थ कारपोरेट ऋण देने में, गुणात्मक आंकड़ों की बड़ी मात्रा जैसे कि कंपनी के वित्तीय एवं मात्रात्मक आंकड़े जैसे फाइलिंग एवं विश्लेषण कॉल रिपोर्टों को निरीक्षित एवं अनिरीक्षित अधिगम कुलनविधियों, दोनों का उपयोग करते हुए मशीन विश्लेषित किए जाते हैं। उपकरण जैसे कि मशीन अधिगम (एमएल), आर्टिफिशियल इंटीलिजेंस (ए आई) और बिग डेटा तथा मशीन बैंकों को बड़े डेटाबेस का विश्लेषण करने के द्वारा पैटर्न को तेजी से पहचानने के लिए योग्यता प्रदान करते हैं, एक गतिविधि जो कि पारंपरिक सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए मानव के लिए आभासी रूप से असंभव होगी। यह विचार नया नहीं है क्योंकि मानक अर्थमितिपरक मॉडल भी पैटर्न पहचानने के लिए उपकरण ही है। नवीनता एल्गोरिथम उनका उपयोग करते हुए आंकड़ों के अत्यंत बड़े समुच्चयों का विश्लेषण करने में ही नवीनता निहित होती है। जैसाकि चित्र 28 दर्शा रहा है, भारत में फिनटेक में अच्छा निवेश हुआ है। अत:

चित्र 28: भारत में फिनटैक में वीसी, पीई और एम एवं ए निवेश गतिविधियां

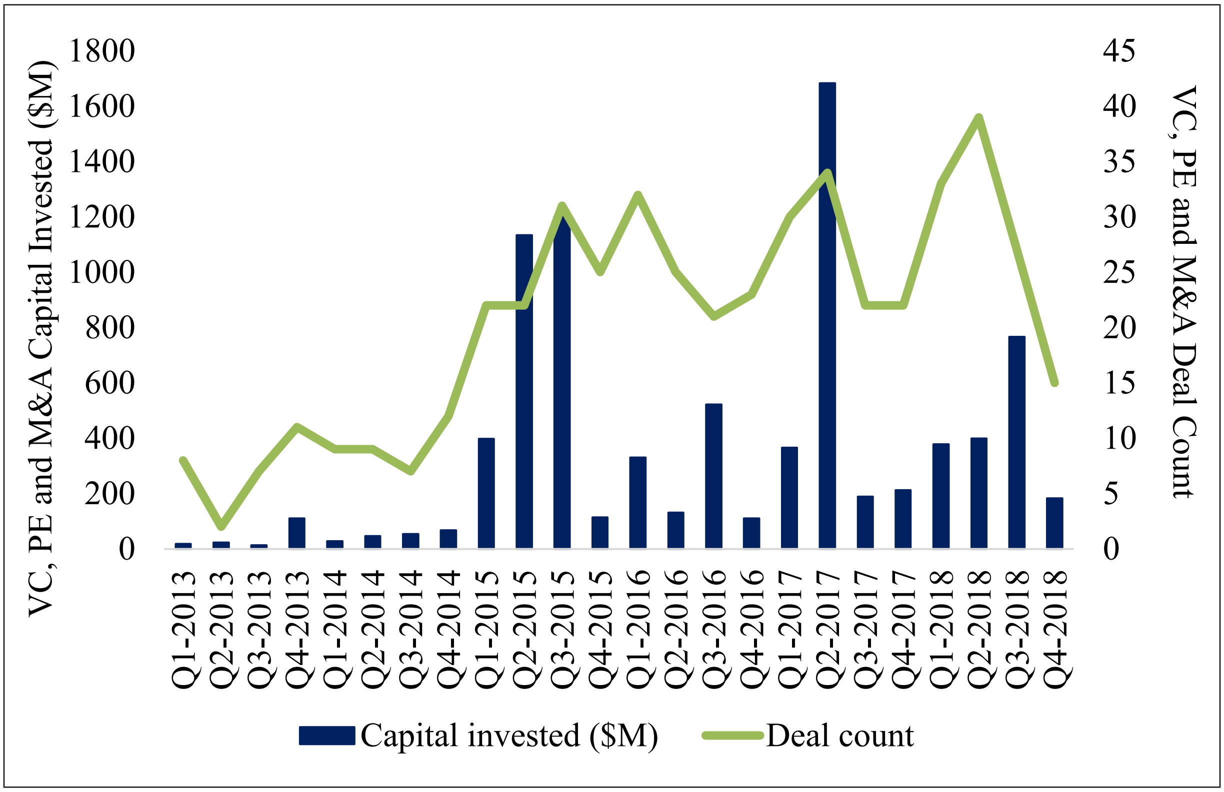

स्रोत: पल्स ऑफ फिनटेक 2018, फिनटेक में निवेश का द्ववी वार्षिक वैश्विक विश्लेषण, केपीएमजी इंटरनेशनल

पीएसबी इस क्षेत्र में सुलभ विशेषज्ञ ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं।

7.42 वर्तमान में, पीएसबी उच्च प्रचालन लागत, हस्तचालित प्रचालनों से अलग प्रक्रिया प्रवाह तथा अधिकरण संबंधी निर्णय लेने से अलग प्रक्रिया प्रवाह जैसी बहुत सी चुनौतियों का सामना करते हैं ये चुनौतियां संभावित उधारकर्ताओं के पूर्वानुमान का मूल्यांकन तथा संपार्श्विक का मूल्य जिसे ये भेज सकते हैं, करने के द्वारा पीएसबी की सख्ती के साथ प्रत्याशित उधारकर्ताओं की क्षमता को जानने में अड़चन डालती है। इन्हें चूककर्ता होने की स्थिति में हानि को कम करने के समर्थकारी अनुबंध को संभावित रूप से लागू करके उधार देने के संबंध में पूरी अवधि के साथ ऋण पश्चात उधारकों की निगरानी करने की भी आवश्यकता है। फिनटेक का उपयोग बैंक को उधारकर्ताओं की बेहतर जांच करने की अनुमति देता है, तथा ब्याज दर निर्धारित करता है जो कि ऋण पश्चात ऋणी के प्रदर्शन का भली भांति पूर्वानुमान लगा सकता है। (राजन, 2015)

7.43 पीएसबी प्रतिनिधि को अपनी मानीटरन भूमिका सौंप कर अपनी क्षमता बढ़ाने में समर्थ होंगे यदि सभी पीएसबी अपने आंकड़े एक निकाय में साझा कर सकेंत हैं। उनके कारपोरेट उधारकर्ता द्वारा धारित निजी सूचना समस्या को कम करने से अनुबंध समस्याएं पैदा होती हैं, क्योंकि उधार देने के पश्चात उधारकर्ता की शोधन क्षमता का मूल्यांकन करना महंगा होता है। (स्टिगलिज एवं वेसस, 1981) इसके अलावा, बैंकों की जांच एवं निगरानी का प्रतिनिधि एक दक्ष तंत्र होना चाहिए। (डायमंड, 1984) यह दक्षता विभिन्न पीएसबी द्वारा सभी सूचना को एक निकाय में इकटठा करने के साथ आगे और बढ़ायी जा सकती है। यह जांच एवं निगरानी की लागत को कम करने का अतिरिक्त लाभ होगा।

7.44 चूंकि सरकार सभी पीएसबी की स्वामी है इसलिए यह पीएसबी को इस आंकड़े को साझा करने का अधिशेष दे सकती है ताकि मितव्ययता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग (ए.आई.एम.एल) का उपयोग करते हुए विश्लेषणात्मक कारोबार में आवश्यक निवेश करने में बड़े पैमाने की मितव्ययता का उपयोग किया जा सकता है। समीक्षा व्यापक एवं विस्तृत रूप से उधारकर्ताओं की जांच एवं निगरानी करने के लिए प्रोद्योगिकियों का उपयोग करने हेतु जीएसटीएन जैसा निकाय जिसे पीएसबीएन (पीएसबी नेटवर्क) कहा जाता है, को स्थापित करने का प्रस्ताव करती है। सभी पीएसबी से आंकड़ों का उपयोग करने जो उल्लेखनीय सूचना लाभ प्रदान करेंगी के अलावा पीएसबीएन कारपोरेट के लिए एआईएमएल रेटिंग विकसित करने हेतु अन्य सरकारी स्रोतों एवं सेवा प्रदाताओं का उपयोग करेगा। एआईएमएल मॉडल को न सिफ तब लगाया जा सकता है जब नए ऋण के लिए कारपोरेट की जांच करनी होती है बल्कि कारपोरेट उधारकर्त्ता की सतत निगरानी के लिए भी लगाया जा सकता है ताकि पीएसबी प्रत्यायोजित मॉनीटर के रूप में सही तरीके से कार्य कर सके। बाक्स 3 वैयक्तिक, एसएमई एवं बड़े कारपोरेशन सहित बैंक ग्राहकों के सभी प्रकारों हेतु प्रस्तावित पीएसबीएन हेतु स्थापत्य तथा सूचना प्रवाह प्रदान करता है।

बॉक्स 5: पीएसबी में फिनटेक के लिए सुझाया गया आर्किटेक्चर तथा समाधान प्रवाह

स्टेमेटिक आर्किटेक्चर

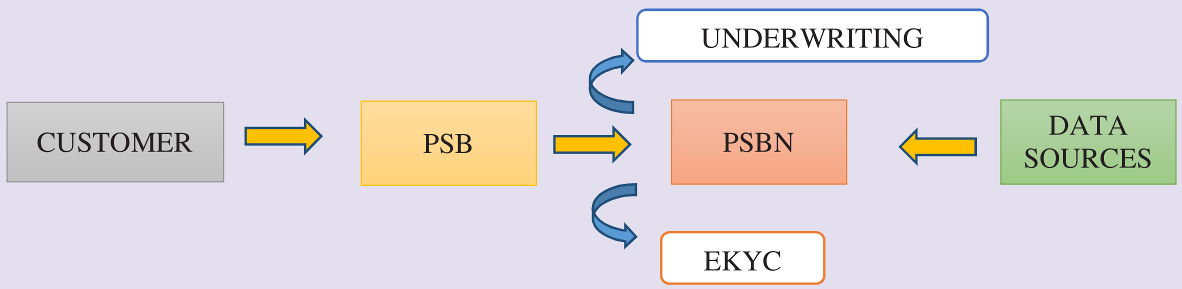

सॉल्यूशन फ्लो:

1. **ग्राहक संपर्क:** ग्राहक पीएसबी के पास पहुंचता है तथा वह उधार लेने के लिए ऋण की राशि और उसके प्रकार की इच्छा जाहिर करता है।

2. **के वाई सी सत्यापन:** पीएसपी उपयुक्त सूचना निकाय को स्थांतरित करता है। निकाय पहचान सत्यान एजेंसियों अर्थात आधार आधारित ईकेवाईसी द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के आधार पर ग्राहकों के लिए मार्गनिदेशों के अनुसार, के वाईसी प्रक्रिया पूरी करेगा। ग्राहकों के लिए के वाईसी की पीएसबी के जरिए ऋण प्रावधान हेतु बैंकों द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए। अत: इंजिन आंकड़ों को मिलाएगा तथा के वाईसी संपुष्टि हेतु पीएसबी को देगा।
3. **आंकड़ा संग्रहण:** इंजिन आगे ग्राहक प्रोफाइल पर आधारित विभिन्न आंकड़ो को संहित स्रोतों से आंकड़े से मिलाएगा। आंकड़ों को इनसे एकत्रित किया जाएगा

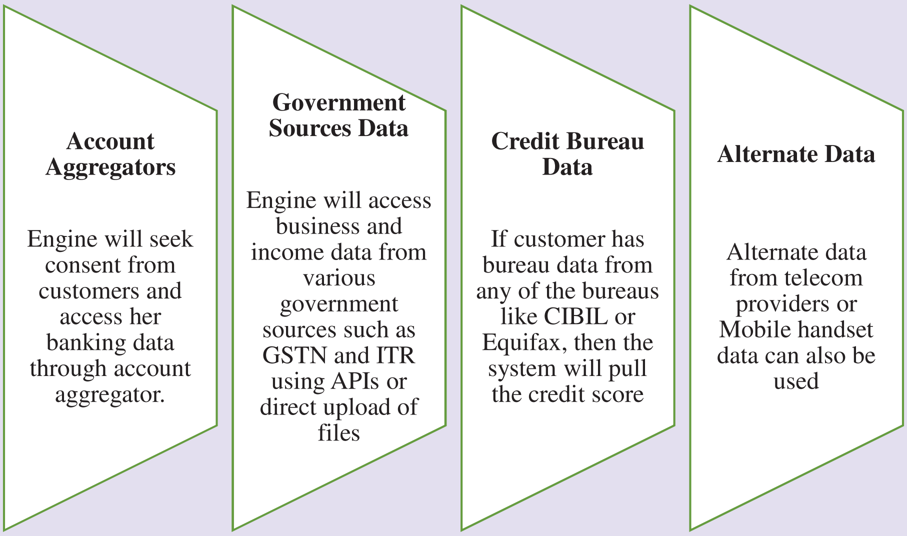

प्रणाली में संपूर्ण क्रेडिट जोखिम का अंकन होगा जो निर्मित मॉडल के आधार पर सभी उपलब्ध डाटा का विश्लेषण करने के बाद ग्राहक की क्रेडिट रूपरेखा (प्रोफाइल) तैयार करेगा। व्यक्ति, एसएमई विभिन्न एआई-एमएल जोखिम अंकन मॉडल तैयार किए जाएंगे।

4. **ऋण प्रावधान:** केवाईसी एवं जोखिम अंकन के आधार पर प्रणाली ऋणों के लिए ग्राहक की पात्रता का निर्धारण करेगी तथा सभी प्रकार की सूचना पीएसबी को अंतरित करेगी। प्राप्त सूचना के आधार पर पीएसबी राशि एवं दिए जाने वाले ऋण की दर के बारे में निर्णय लेगा।

महत्वपूर्ण सहभागी:

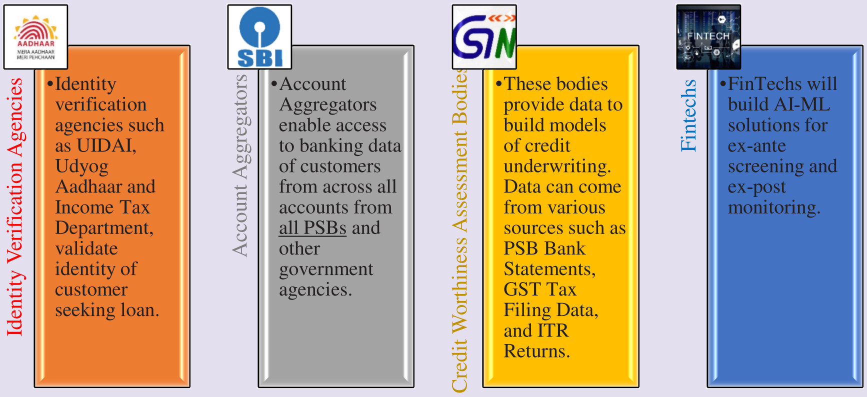

7.45 पीएसबीएन का लाभ यह होगा कि यह उस डाटा का उपयोग कर सकेगा जिसका का विगत 50 वर्षों के दौरान बेहतर जोखिम अंकन समाधान का सृजन करने के लिए उपयोग किया है और जो डाटा उनकी धरोहर है। पीएसबीएन का उपयोग करते हुए, वे अपने कारपोरेट ग्राहकों को ऋण के लिए बेहतर जोखिमअंकन करने मे सक्षम होंगे। क्रेडिट अंडरराइटिंग (जोखिम अंकन) पर बेहतर निर्णय लेने से अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का

भार कम होगा, तथा इसके साथ-साथ धोखाधाड़ी के प्रत्येक पीएसबी की उच्च प्रचालन लागत उन्हें उधार देने की समग्र प्रक्रिया ''एंड-टू-एंड'' को स्वचालित करने में मदद करेगी। यह प्रक्रिया अपनाए जाने से पीएसबी यथाशीघ्र निर्णय लेने में सक्षम होगा, ऋण अनुप्रयोगों को शीघ्रता से संसाधित करेगा, और इस प्रक्रिया को पूरा करने मे लगने वाली समय अवधि को कम करेगा (टीएटी)। इस प्रक्रिया के बेहतर अनुपालन से एनपीबी के साथ पीएसबी बेहतर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। वास्तव में, पीएसबीएन सूचना संबंधी लाभ प्रदान कर सकते हैं, जिनका लाभ चाहकर भी एनपीबी नहीं उठा सकते।

पीएसबी में कर्मचारी हिस्सेदारी का प्रश्न

7.46 कर्मचारियों को मुख्यत: पर वेतन के रूप में भुगतान किया जाता है। क्योंकि वर्तमान में पीएसबी कर्मचारियों के ऐसे भी दावे हैं जो ऋण अनुबंध से मिलते-जुलते हैं कि उनका भुगतान बैंकों द्वारा किया जाना है। ऐसी निर्धारित प्रति संविदाओं के माध्यम से कर्मचारियों को किए जाने वाले भुगतान के संदर्भ में कर्मचारी, राज्य द्वारा बैंक के संकट के समय में अपने उनके (और सेवानिवृति के बाद पेंशन) के संबध में कल्याणकारी वायदे पर भरोसा करते हैं। वित्त अर्थशास्त्रियों की भाषा में ऐसे कर्मचारियों के आन्तरिक देनदारियां'' होती है जो उनको अनुदारवाद के प्रति प्रेरित करती है तथा यहां तक कि वरिष्ठ कार्यपालकों में भी जोखिम लेने के प्रति सुरक्षित मार्ग अपनाने को महत्त्वपूर्ण बना देती है। (अर्थात् एडमन्स एवं ल्यू, 2011) कर्मचारियों की वर्तमान सपाट प्रतिकर संविदाओं एवं सतर्क एजेंसियों द्व ारा कार्योत्तर मॉनीटरन से होने वाले दबाव को देखते हुए यह शायद ही आश्चर्यजनकहै कि राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों के कर्मचारी जोखिम लेने एवं नवाचार की बजाए सुरक्षा एवं संरक्षणवाद को तरजीह देते हैं। इस समस्या का दीर्घावधि समाधान कर्मचारीओं को पीएसबी में स्टॉक देकर सक्षम बनाना है।

7.47 कर्मचारियों को बैंकों में स्वामी बनने में सक्षम बनाने एवं सतत् रूप में जोखित उठाने एवं नवीकरण को अपनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी पण के एक हिस्से को कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (ईएसओपी) के माध्यम से संगठन के सभी स्तरों पर अच्छा निष्पादन करने वाले कर्मचारियों को अंतरित किया जा सकता है।

7.48 कर्मचारियों की पीएसबी में आंशिक-सहभागिता से एजेंसी समस्याओं में कमी आएगी। ऐसा इसीलिए होगा चूंकि कर्मचारी, जिनके शेयर हैं, को इक्विटी के बाजार मूल्य को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, चूंकि उनकी प्रत्येक प्रतिप्राप्ति शेयर मूल्य पर निर्भर करती है। अन्य लाभों में कर्मचारी से मालिक वाली मनोदशा में परिवर्तित करना शामिल है। कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना (ईएसओपी) के माध्यम से पीएसबी के नए मालिकों के किसी एक ब्लॉक, जो कर्मचारी के निष्पादन पर निभ्रर है, का गठन कर सकते हैं। संगठन के सभी स्तरों पर प्रेरित, सक्षम कर्मचारियों का स्वामित्व उन कर्मचारियों को मूल्य संर्वधन के लिए वित्तीय इनाम देगा, यह प्रोत्साहन पीएसबी के लाभ से समन्वित होगा तथा कर्मचारियों के लिए उपक्रम स्वामित्व की मनोदशा सृजित करेंगे।

प्रौद्योगिकी पर आधारित बेहतर प्रतिभा एवं संगठन की आवश्यकता

7.49 एक संबंधित विषय बैंक पदाधिकारियों की भर्ती की प्रक्रिया लेकर है। उदाहरण के लिए पीएसबी परिसरों से सीधे व्यवसायिक एमबीए की भर्ती नहीं कर सकते। ऊपर दिए गए फिनटैक विच्छेदों को देखते हुए पीएसबी को अत्याधुनिक भर्ती व्यवहारों में सक्षम बनने की आवश्यकता है जिसमें व्यावसायिकों के पारशिवक प्रवेश एवं प्रौद्योगिकी, डाटा विज्ञान, वित्त एवं अर्थशस्त्र विषयों में कौशल प्राप्त व्यासायिक स्तर पर प्रशिक्षित प्रतिभाओं को प्रवेश स्तर पर अनुमति दी गई हो। कर्मचारियों के लिए उपलब्ध बड़े स्वामित्व स्टैक उद्योग में बेहत्तर प्रतिभा को आकर्षित करने में रूकावट नहीं होगी। फिनटैक एवं डाटा विज्ञान में हुई प्रगति से परीक्षण के लिए नवाचार, प्रयोगशालाएं, प्रेरक, वेन्चर आर्म्स एवं सैण्डवॉक्स जैसे समग्र रूप से नए विषय उपलब्ध हैं जो बड़े औषध और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्पष्ट हुए हैं।

7.50 विघटनकारी प्रक्रियाओं के माध्यम से विघटनकारी नवाचारों को अपनाना मुश्किल है। इसके लिए सभी स्तरों पर जोखिम उठाने वाली एक डिग्री, एक लचीली मानव शक्ति अधिग्रहण रणनीति की आवश्यकता होती है, और पूरक प्रोत्साहन अवसंरचनाओं की भी, जो उदाहरण के लिए जो अधिक उच्च-शक्ति वाले प्रोत्साहन की पेशकश करती है जो सफलता के लिए अधिक वेतन

का प्रस्ताव करती हैं। पीएसबी के कर्मचारियों को सरकार द्वारा एक उदार स्वामित्व का प्रस्ताव उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले बैंकिंग पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए प्रौत्साहन संरचना प्रदान करने में सहायता करेगा और जिसके कारण उनकी मानव संसाधन अधिग्रहण रणनीतियों में सुधार होगा।

निष्कर्ष

7.51. आज भारत का बैंक क्षेत्र अर्थव्यवस्था के अनुपात मे बहुत छोटा है। बड़ी अर्थव्यवस्था की संवृद्धि में सहयोग के लिए एक दक्ष बैंकिंग क्षेत्र आवश्यक है। ऐतिहासिक रूप से पिछले 50 वर्षों में विश्व की 5 विशालतम अर्थव्यवस्थाओं को सदैव अपनी बैंक व्यवस्था का सक्रिय का सहयोग मिला है। भारत की संवृद्धि में आवश्यक सहयोग देने मे समर्थ होने के लिए कम से कम 6 बैंकों को विश्व के विशालय 100 के वर्ग में अपना अच्छा स्थान बनाना होगा। पी.एस.बी. का देश के बैंकिंग क्षेत्र में 70 प्रतिशत अंश होने के नाते देश के अर्थतन्त्र को बढ़ावा देने और विकास के संपोषण का दायित्व भी इन्हीं पर आता है। किन्तु सभी निष्पादन कसौटियों पर या बैंक अपने समकक्षों की तुलना में निकृष्ट ही पाए गए हैं। नरसिंहन समिति (1991–1997), राजन समिति 2007 और पी.जे. नायक समिति (2014) ने पीएसबी की दक्षता सुधारने के लिए अनेक सुझाव दिए हैं ये इन्हें देश की 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की ओर यात्रा में सहायता करने के लिए अधिक सक्षम बना पाएंगे। इन सभी समीक्षा ने सभी बैंक कार्यों में फिनटेक तथा कर्मचारी स्टॉक स्वामितव का सुझाव पीएसबी में सभी स्तरों पर दक्षता बढ़ाने के लिए दिया है। सुझावों पर गंभीरता पूर्वक विचार कर एक समय बद्ध कार्य-योजना बनाई जानी चाहिए। बैंकिंग व्यवस्था में स्वच्छता लाने के सथा आईबीसी जैसी विधिक रचना का समावेश होना चाहिए तथा बैंक व्यवस्था को विस्तृत होकर देशकी अर्थव्यवस्था में सहायक होना चाहिए।

CHAPTER AT A GLANCE

- वर्ष 2019 में भारत ने बैंक राष्ट्रीयकरण की 50वीं वर्षगांठ संपन्न की है। अत: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में कार्य करने वाले 3,89,956 अधिकारियों 2,95,380 लिपिकों एवं 1,21,647 सब-स्टॉक, के प्रयासों का उत्सव मनाना उचित हैं तथापि पीएसबी की वस्तुपरक समीक्षा भी आवश्यक है।
- भारत ने वर्ष 1969 से विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए बहुत त्वरित गति से तरक्की की है। फिर भी, भारत के बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के आकार के अनुरूप असंगत रूप से अविकसित रहा है। उदाहरण के लिए विश्व के 100 शीर्ष बैंकों में से भारत में केवल एक बैंक है किसी ऐसे देश के अनुरूप जो इसके आकार की तुलना में बहुत छोटे हैं फिनलैंड (लगभग 1/11वां), डेनमार्क (1/8वां), नार्वे (1/7वां) आस्ट्रिया (1/8 वां) एंव बेल्जियम (लगभग 1/6)। स्वीडन (1/6वां) एंव सिगांपुर (1/8वां) जैसे देशों में वैश्विक बैंको की संख्या भारत में उपलब्ध ऐसी बैंक संख्या से तीन गुणा है।
- बड़ी अर्थव्यवस्था में प्रगति करने के लिए प्रभावी बैंकिंग क्षेत्र की आवश्यकता है। ऐतिहासिक रूप में, पिछले 50 वर्षों में शीर्ष पांच-अर्थव्यवस्थाओं को सदैव उनके बैंकों ने सहायता प्रदान की है।
- चूंकि भारतीय बैंकिंग में पीएसबी के पास बाजार शेयर का 70 प्रतिशत हिस्सा है, अत: भारतीय अर्थव्यवस्था को सहायता प्रदान करने एवं इसकी आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी भ्सी इनकी है। फिर भी, प्रत्येक निष्पादन मानदंड के स्तर में पीएसबी अपने सहयोगी समूहों की तुलना में अक्षम है। वर्ष 2019 में, पीएसबी में निवेशत कर दाता की राशि के प्रत्येक रुपए में, औसतन 23 पैसे की क्षति हुई है। इसकी तुलना में एनपीबी में निवेशित कर दाता की राशि के प्रत्येक रुपए में, औसतन 9.6 पैसे का लाभ हुआ है। इसके अलावा, पिछले काफी वर्षों से पीएसबी की प्रगति एनपीबी की तुलना में काफी धीमी रही है।

- समीक्षा में ऐसे सुझाव दिए गए हैं जो पीएसबी को अधिक सक्षम बना सकते हैं ताकि वे 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते राष्ट्र की अच्छी तरह से सहायता कर सकें।
- कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने तथा उनके हितों का बैंक के साथ शेयर धारकों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए बैंक कर्मचारियों को कर्मचारी स्टॉक स्वामीत्व के माध्यम से हिस्सेदारी देने के साथ-साथ कर्मचारियों के ब्लॉकों के अनुपात में बोर्ड में उनको अनुपाती प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।
- बड़े स्तर के डाटा, कृत्रिम आसूचना एवं क्रेडिट निर्णयों में मशीन लर्निगं, विशेषकर बड़े ऋण दाताओं संबंधी, का प्रयोग करने के लिए जीएसटीएन प्रकार का एक प्रतिष्ठान स्थापित किया जाना चाहिए। चूंकि सरकार सभी पीएसबी की मालिक है, अत: सरकार को पीएसबी द्वारा अपने कारोबार के दौरान पैदा किए गए डाटा को प्रयोग करने का अधिकार है। अत: प्रायोजक के रूप में सरकार को इस प्रतिष्ठान की स्थापना करनी चाहिए जिससें बड़ी डाटा तकनीकों का प्रयोग करके निर्णय लेने में सक्षम बनकर सभी पीएसबी से लिए डाटा को समाकलित हो। त्रुटिपूर्ण पैटर्न, जिनका खुलासा शक्तिशाली तकनीक कर सकती है। बचने वाले किसी भी बेईमान प्रायोजक की क्षमता से परे हैं। अत: ऋणदाताओं, विशेषकर बड़े स्तर वाले, के बेहत्तर मूल्यांकन एवं देखरेख को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे निवेश महत्वपूर्ण हैं।
- बैंकिंग प्रणाली और आवश्यक विधिक फ्रेम वर्क तथा दिवालिया और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) को स्वच्छ बनाते हुए बैंकिंग प्रणाली को अर्थव्यवस्था के समर्थन में दक्षता उन्नयन पर अवश्यमेव ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

संदर्भ

Chakrabarty, K.C., (2013), Two decades of credit management in banks: Looking back and moving ahead (Address by Dr. K. C. Chakrabarty, Deputy Governor, Reserve Bank of India).

Diamond, Douglas W. "Financial Intermediation and Delegated Monitoring." The Review of Economic Studies 51, no. 3 (1984): 393-414. Accessed January 25, 2020. www.jstor.org/stable/2297430.

Edmans, Alex and Liu, Qi, Inside Debt (June 29, 2011). Review of Finance, Vol. 15, No. 1, pp. 75-102, January 2011; EFA 2007 Ljubljana Meetings Paper. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=758508.

Mishra, Prachi and Prabhala, Nagpurnanand and Rajan, Raghuram G., The Relationship Dilemma: Organizational Culture and the Adoption of Credit Scoring Technology in Indian Banking (March 5, 2019). Johns Hopkins Carey Business School Research Paper No. 19-03. Available at SSRN: https://Ssrn.com/Abstract=3347299.

Narasimhan Committee I (1991), Report of the Committee on Financial Systems, Reserve Bank of India.

Narasimhan Committee II (1998), Report of the Committee on Banking Sector Reforms, Reserve Bank of India.

Nayak Committee (2014), Report of the Committee to Review Governance of Boards of Banks in India, Reserve Bank of India.

Rajan Committee (2007), Report of the Committee on Financial Sector Reforms, Government of India.

Rajan, U., Seru, A., and Vig, V. (2015). The Failure of Models That Predict Failure: Distance, Incentives, and Defaults. Journal of Financial Economics, 115, 237-260.

Stiglitz, Joseph E., and Andrew Weiss. "Credit Rationing in Markets with Imperfect Information." The American Economic Review 71, no. 3 (1981): 393-410. Accessed January 25, 2020. www.jstor.org/stable/1802787.